04 - ट्रंप की नीतियों ने गिराई अमेरिका की साख

05 - जीवन का सबसे कठिन, सबसे सुंदर और सबसे सच्चा इस्तीफा

A Daily News Magazine
इंदौर
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026

06 - प्रशासनिक के साथ नैतिक सुधार भी जरूरी

07 - सफलता की नई ऊंचाईयों को छूने पूरी लगन और मेहनत से...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 297, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

बांग्लादेश : हिंसक छात्र आंदोलन के दो साल बाद हासिल क्या हुआ?

दीप हलदर

जुलाई का महीना बांग्लादेश के लिए काफी अहम होता है। यह देश के आत्ममंथन का भी महीना है। 2024 में जुलाई के दौरान पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैले छात्र आंदोलन ने अगस्त की शुरुआत तक तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी। उसके बाद से बीते दोनों जुलाई महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं 2024 के आंदोलन से निकली छात्र नेताओं की नई पार्टी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) समेत कई दलों ने शहीद मीनार जैसे प्रमुख स्थानों पर रैलियां कीं।

लेकिन इस जुलाई कुछ बदल गया है। अब 'जुलाई' शब्द के साथ अपमानजनक गाली वाला शब्द 'जुलाई CDI' जुड़ गया है। एक तरफ NCP और बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी अब साथ आ गए हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश सिर्फ शेख हसीना के सवाल से नहीं, बल्कि एक बड़े सवाल से जूझ रहा है। आखिर जुलाई 2024 में इतना खून-खराबा किस लिए हुआ था?

इस साल 1 जुलाई को बांग्लादेश की मशहूर अभिनेत्री और निर्देशक मेहर अफरोज शाओन ने सोशल मीडिया पर 2024 के छात्र आंदोलन को 'जुलाई CDI' कहा। 'CDI' बंगाली भाषा का एक आम गाली वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों जगह होता है।

4 जुलाई को 'द डेली स्टार' ने खबर दी कि शाहबाग पुलिस स्टेशन में तीन महिलाओं अभिनेत्री मेहर अफरोज शाओन, माहिया माही और शांता फरजाना के खिलाफ जनरल डायरी दर्ज कराई गई है। उन पर सोशल मीडिया पर जुलाई आंदोलन का मजाक उड़ाने और उसके स्मारक का अपमान करने का आरोप है।

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'शिकायत में कहा गया है कि शांता फरजाना ने जुलाई स्मारक पर जूता फेंका। वहीं शाओन ने जुलाई आंदोलन को 'पहले से तय किया गया कार्यक्रम' बताया, जबकि माहिया माही ने इस आंदोलन में शामिल लोगों और संगठनों का मजाक उड़ाया।'

इसके बाद से बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर कई लोग छात्र आंदोलन को 'जुलाई CDI' कहने लगे हैं। फेसबुक पर वायरल एक पोस्ट में जॉयतुर्जा चौधरी नाम का यूजर 'जुलाई CDI' कहते हुए इस आंदोलन के समर्थकों को मिडिल फिंगर दिखाता नजर आता है। वह उन लोगों का भी विरोध करता है जो बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम, उसके नेताओं और जमात-ए-इस्लामी समेत दूसरे कट्टरपंथी संगठनों को नजरअंदाज करते हैं।

दूसरी तरफ जवाब में 'मुजीब CDI' शब्द भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका इस्तेमाल छात्र आंदोलन का मजाक उड़ाने वालों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। मशहूर यूट्यूबर इलियास हुसैन ने पोस्ट कर कहा कि जो लोग 'जुलाई CDI' कह रहे हैं, उन्हें जवाब देने के लिए अब 'मुजीब CDI' और 'हसीना CDI' कहा जाएगा।

बांग्लादेश के सेवानिवृत्त राजनयिक मोहम्मद हारून अल राशिद का मानना है कि सोशल मीडिया पर जुलाई आंदोलन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, क्योंकि लोगों को अब लगने लगा है कि छात्र आंदोलन की आड़ में इस्लामिक ताकतें मजबूत हो गईं।

राशिद ने कहा, 'पहले मोहम्मद यूनुस ने जमात-ए-इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों को खुली छूट दी। अब तारिक रहमान भी इसी नीति पर चल रहे हैं और इस्लामिक ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में देश का एक बड़ा वर्ग बांग्लादेश जिस दिशा में जा रहा है, उससे नाराज है।' बांग्लादेश के राजनीतिक पत्रकार साहिदुल हसन खोकों का कहना है कि जुलाई आंदोलन की दूसरी बरसी पर भी शेख हसीना का सवाल बांग्लादेश का पीछा नहीं छोड़ रहा। हसीना ने कहा है कि वह इस दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। इससे देश बंटा हुआ है। तारिक रहमान सरकार दबाव में है। एक अदालत ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर उन्हें काफी समर्थन मिल रहा है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अब उन लोगों से निराश हो चुका है, जिन्हें लगता था कि हसीना को हटाने से बांग्लादेश बेहतर हो जाएगा। सरकार की कार्रवाई के बावजूद अब पूरे बांग्लादेश में हसीना के समर्थन में खुलेआम जुलूस निकल रहे हैं। यह तब हो रहा है, जब तारिक रहमान सरकार ने अवामी लीग की चुनावी राजनीति में वापसी के लगभग सभी कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं।'

जुलाई आंदोलन पूरे बांग्लादेश को एकजुट नहीं कर पाया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज भी लोगों के मन में सवाल है कि इस आंदोलन की अगुवाई किसने की और इसका मकसद क्या था। हर क्रांति का एक चेहरा होता है। 2024 के जुलाई आंदोलन का चेहरा उस समय 23 साल के अबू सईद थे। 16 जुलाई को सईद रंगपुर की बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन करते समय वो पुलिस की गोलियों का शिकार हुए।

सईद की मौत ने जुलाई आंदोलन को नई ताकत दी। भारत में अबू सईद के बढ़ते प्रभाव के कारण चिंता बढ़ गई। क्योंकि वो इस्लामी इतिहास, जिहाद और शहादत से प्रेरणा पाते थे। लेकिन अबू सईद अचानक क चे ग्वेरा जैसी छवि वाले नेता बन गए थे। पूरे आंदोलन को शुरू से ही जमात का समर्थन था। आरक्षण विरोधी आंदोलन सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद हसीना को हटाकर देश को उनके कट्टर विरोधियों के हाथों में सौंपना था। हसीना को पहले ही इसकी चेतावनी दी गई थी।'

दिलचस्प बात यह है कि जुलाई आंदोलन से बनी राजनीतिक पार्टी एनसीपी ने फरवरी 2026 के आम चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन के बाद एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी के भीतर संकट पैदा हो गया। इसके बाद यह शक और गहरा हो गया कि जुलाई आंदोलन शुरू से ही देश की सत्ता पर कब्जा करने की एक इस्लामवादी साजिश था। अब, जुलाई आंदोलन की दूसरी बरसी पर बांग्लादेश एक बड़े सवाल का सामना कर रहा है. आखिर इतने खून-खराबे से हासिल क्या हुआ?

डेली वादा के लिए शफीकुल इस्लाम ने लिखा, 'ढाका की सड़कों पर लोगों ने सिर्फ एक शोषक सत्ता को हटाकर दूसरी शोषक सत्ता लाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली थी। लोगों की उम्मीदें इससे कहीं बड़ी थीं। वे चाहते थे कि देश बदले की राजनीति के पुराने चक्र से बाहर निकले और एक जवाबदेह व्यवस्था बने।' लेकिन उनके मुताबिक जुलाई आंदोलन सिर्फ सरकार बदलने तक सीमित रह गया। शासन चलाने का तरीका और उसकी सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

पेपर लीक रोकने

सख्त कानून लोकसभा में पास

● इसमें 7 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान ● राज्यसभा में वंदेमातरम से जुड़ा संशोधित बिल भी पास

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल पास हो गया। अब जन-गण-मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। नए कानून में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों के प्रावधान हैं।

● **राहुल की 50 मिनट की स्पीच, संसद में जमकर हंगामा-** इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े बिल पर 50 मिनट स्पीच दी। उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द बोले। फिर कहा कि गृहमंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए। इसको लेकर सत्तापक्ष ने जमकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 बार खड़े होकर राहुल को टोका और संसदीय नियम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए।

● **राहुल बोले-देश का भविष्य सड़कों पर उतरा-** राहुल ने कहा, 'देश का भविष्य सड़कों पर उतरा। प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत नहीं थी। वे केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। अगर भाजपा के मेरे मित्र अपने बच्चों से पूछें कि उनके भाई-बहन जो कर रहे हैं, उसके बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का भी समर्थन ही मिलेगा।' लोकसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। पेपर लीक से जुड़े बिल पर आज लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है। मंगलवार को बिल पर 9 घंटे बहस हुई थी। पहले दिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव बहस में शामिल हुए।

● **गृह मंत्री ने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए-** राहुल गांधी ने इस दौरान स्टूडेंट, इंडियट के साथ ही तीसरी कैटेगरी अंधभक्त का जिक्र किया। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही हंगामा शुरू हो गया। किरेन रिरिजू ने इसे सदन की कार्यवाही से हटाने की अपील की, जिसके बाद स्पीकर ने इसे हटा दिया। इसके बाद राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कमेंट किया जिस पर हंगामा हो गया।

दतिया उपचुनाव में मतदान आज

प्रत्याशियों ने अंतिम दिन दी घर-घर दस्तक, वोट देने की अपील

भोपाल। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार शाम प्रचार थमने के साथ ही चुनावी मुकाबला अब घर-घर संपर्क और बूथ मैनेजमेंट पर आ गया है। भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार के आखिरी दौर में पूरी ताकत झोंक दी। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, वहीं मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने अपने प्रभाव वाले इलाकों में पैदल जनसंपर्क किया। दोनों दलों की सक्रियता के बावजूद मतदाताओं ने अब तक चुप्पी साध रखी है। इस चुनाव में विकास, स्थानीय समस्याएं, सरकार के कामकाज और प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि जैसे मुद्दे हैं, लेकिन जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट मुकाबले की दिशा तय करने वाले प्रमुख फैक्टर माने जा रहे हैं। दतिया विधानसभा में करीब 2.20 लाख मतदाता हैं।

सुप्रभात

आजकल भाई से भाई डर रहा है
कोई घरवाला ही साजिश कर रहा है
बोलता है वो झूठ को सच की तरह,
छल कपट का तो वो कारीगर रहा है
जख्म देकर बेचता वो शख्स मरहम
ऐसा वो बेशर्म सौदागर रहा है
कोशिशें है उसकी तुझको बांटने की
और तेरा ही यकीं उस पर रहा है
ख्वाब में तू देखता जो सुनहरा कल,
हाथ में उसके वही कल मर रहा है
वो समझता है तुझे कतरा जरा सा
जबकि तेरी हस्ती से सागर रहा है
भर रहा दिल में तेरे वो नफरती सोच,
कांच के घर में छिपा पत्थर रहा है
वो मुहाफिज है मगर कैसी हिफाजत,
खेत खाती बाढ़ सा मंजर रहा है
अब मुहब्बत की करें उम्मीद किससे,
फूलवाला भी दिखा खंजर रहा हैं।

- के.के.पुरोहित

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बोले डॉ. मोहन यादव - एमपी में जल्द 1000 के करीब होंगे बाघ

कहा- वन्यजीव संरक्षण हमारी प्राथमिकता, हम नदियों में घड़ियाल छोड़ रहे

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में बाघ संरक्षण का अग्रणी राज्य है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में 785 बाघ थे और आगामी गणना में यह संख्या एक हजार के करीब पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी पर यदि कहीं बाघ इंसानों के सबसे नजदीक रहते हैं तो वह भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार नदियों में घड़ियालों का संरक्षण भी कर रही है। पहले घड़ियालों का लाभ राजस्थान को अधिक मिलता था, लेकिन अब प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में छोड़े गए घड़ियाल यहीं सुरक्षित रहें।

गुरु पूर्णिमा अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व- मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं, बल्कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला उत्सव है। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से विश्वगुरु की अवधारणा पर चलता आया है और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का उदाहरण देते हुए कहा कि पेड़ों में प्राण होने की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से स्वीकार की जाती रही है।

टाइगर बचाना, अपना जीवन बचाने जैसा

कार्यक्रम में वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन ने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व हमेशा वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा जंगल वही माना जाता है, जहां बाघ, बाघिन और उनके शावक सुरक्षित हों। बाघों का संरक्षण प्रकृति और मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए नए वाहनों का लोकार्पण किया तथा वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभागीय प्रकाशनों का विमोचन, सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन पर आधारित वृत्तचित्रों के टीजर जारी किए और राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के पद्मश्री सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वन सुरक्षा समितियों, ईको विकास समितियों, ग्राम वन समितियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। समारोह में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

यूक्रेन में जहाज के पास हमले में 13 भारतीय फंसे

● 15 क्रू मेंबर सवार थे, लगातार ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हो रहे

कीव (एजेंसी)। यूक्रेन में चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर जहाज के पास हमले में 13 भारतीय फंस गए हैं। 'एमवी अमीर 1' नाम का जहाज लगातार हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच फंस गया है। इसके बाद इंडियन सीमेन यूनियन ने इस मामले में तुरंत मदद की अपील की है। यूनियन के मुताबिक, जहाज पर कुल 15 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 13 भारतीय नाविक शामिल हैं। जहाज बेहद खतरनाक हालात में फंसा हुआ है। उसके आसपास लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश हो रही है, जिससे चालक दल के सदस्य हर पल सीधे हमले की आशंका में जी रहे हैं। यूनियन ने भारत सरकार, जहाज के मालिक, फ्लैग स्टेट और सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि नाविकों की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित की जाए और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापस लाया जाए।

दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की साजिश नाकाम

● सुरक्षाबलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में बरामद हुआ हथियारों का जखीरा

श्रीनगर (एजेंसी)। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से बुधवार को एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिले के तांत्रेपोरा-सुरसनू के घने बाग वाले इलाके में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। इस बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन की कहानी शुरू हुई एक सटीक खुफिया सूचना से। जम्मू-कश्मीर पुलिस को अपने सोर्स से जानकारी मिली थी कि तांत्रेपोरा-सुरसनू के बाग वाले क्षेत्र में कुछ संदिग्ध सामग्री छिपाई गई है। इस इनपुट को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस सूचना के आधार पर कुलगाम पुलिस, भारतीय सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 18वीं बटालियन ने मिलकर इलाके को घेरने की रणनीति बनाई।

बाग के चप्पे-चप्पे में चला सर्च ऑपरेशन

बुधवार सुबह से ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तांत्रेपोरा-सुरसनू के बाग क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बाग की आड़ में छिपाए गए हथियारों को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर एक-एक जगह को बारीकी से खंगाला। कई घंटों तक चले इस सघन सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार जवानों को वह कामयाबी मिली जिसका इंतजार था। बाग के अंदर एक जगह से हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने आने वाले दिनों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस जखीरे को यहां छिपा कर रखा था। सुरक्षा बलों ने बरामद किए गए सभी हथियारों और गोला-बारूद को तुरंत अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 30 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

गुरु पूर्णिमा पर पीतांबरा पीठ में उमड़ा आस्था का सैलाब

10 हजार गुरु दीक्षित साधकों ने किया गुरु पादुका पूजन, पांच दिवसीय साधना के समापन पर वैदिक विधि-विधान से हुआ गुरु पूजन, उपचुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था रही अभेद्य

दतिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्वविख्यात श्री पीतांबरा पीठ बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का विराट केंद्र बना रहा। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में गुरु दीक्षित साधकों, श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां पीतांबरा के दर्शन कर गुरु परंपरा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। पूरे दिन पीठ परिसर धार्मिक अनुष्ठानों, गुरु वंदना, मंत्रोच्चार और भक्ति के वातावरण से सराबोर रहा।

पीठ से जुड़े साधकों के अनुसार इस वर्ष भी लगभग 7 हजार से 10 हजार गुरु दीक्षित साधकों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पादुका पूजन एवं विशेष अनुष्ठान में भाग लिया। साधकों ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए वैदिक परंपरा के अनुसार गुरु पूजन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और विश्व कल्याण की कामना की।

गुरु पूर्णिमा से लगभग पांच दिन पूर्व ही गुरु दीक्षित साधक दतिया पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान वे पीठ परिसर में रहकर नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप, ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बने। साधकों के रहने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं श्री पीतांबरा पीठ ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष पूजन के साथ इस पांच दिवसीय साधना का समापन हुआ।

निर्धारित समय पर गुरु परंपरा के अनुरूप गुरु पादुका पूजन एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। श्रद्धालुओं ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रद्धापूर्वक पूजन किया।

उपचुनाव के चलते सुरक्षा के विशेष इंतजाम

इस बार गुरु पूर्णिमा के आयोजन के दौरान 30 जुलाई को होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती। पुलिस एवं प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए तथा आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट व्यवस्था लागू की कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु मां पीतांबरा के दर्शन एवं पूजन के बाद मंदिर परिसर अथवा शहर में अनावश्यक रूप से नहीं रुक सकेंगे। उन्हें दर्शन के उपरांत तत्काल अपने गंतव्य के लिए रवाना होना होगा। उपचुनाव के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था से बचने के उद्देश्य से इस वर्ष यह विशेष व्यवस्था लागू की गई।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 'संपर्क अभियान 2026' को मिली बड़ी सफलता

3721 शिविरों में 1 लाख 66 हजार 643 शिकायतों का हुआ निराकरण

भोपाल। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का उनके घर के नजदीक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित 'संपर्क अभियान 2026' को उल्लेखनीय सफलता मिली है। 14 मई से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान में भोपाल एवं ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में अब तक 3721 विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1 लाख 66 हजार 643 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- भोपाल रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त भोपाल में 274 शिविरों में 17,078 शिकायतों का निराकरण किया गया। बैतूल वृत्त में 329 शिविरों में 18,912 शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ओ एंड एम) वृत्त में 189 शिविरों में 6,236 शिकायतों का निराकरण, हरदा वृत्त में 99 शिविरों में 14,469 शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 250 शिविरों में 21,098 शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 190 शिविरों में 13,392 शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 270 शिविरों में 3,717 शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 240 शिविरों में 5,955 शिकायतों का निराकरण तथा विदिशा वृत्त में 153 शिविरों में 8,627 शिकायतों का निराकरण किया गया।

ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- ग्वालियर रीजन के अंतर्गत शहर वृत्त ग्वालियर में 221 शिविरों में 4,475 शिकायतों का निराकरण किया गया। अशोकनगर वृत्त में 110 शिविरों में 11,435 शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 211 शिविरों में 4,647 शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 130 शिविरों में 5,774 शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 190 शिविरों में 7,575 शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ओ एंड एम) वृत्त में 186 शिविरों में 3,476 शिकायतों का निराकरण, मुरैना वृत्त में 289 शिविरों में 9,867 शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 140 शिविरों में 4,315 शिकायतों का निराकरण तथा शिवपुरी वृत्त में 250 शिविरों में 5,595 शिकायतों का निराकरण किया गया।

इन शिकायतों और सेवाओं पर हुआ त्वरित काम- शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग एवं अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही मात्र 5 रुपये में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थायी कनेक्शन विच्छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवाईसी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, बंद/खराब मीटर बदलना, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निराकरण, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज संबंधी समस्याओं का समाधान, ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों का निराकरण, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि जमा कराने सहित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्रदान किए गए।

संक्षिप्त समाचार

अमृतपाल सिंह की रिहाई को लेकर चंडीगढ़ में बवाल

वारिस पंजाब दे के नेता-कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई वॉटर कैनन

चंडीगढ़ (एजेंसी)। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के बीच वारिस पंजाब दे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई को लेकर चंडीगढ़ में बुधवार को प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने वारिस पंजाब दे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं की पुलिस से झड़प हुई। कार्यकर्ता वॉटर कैनन की गाड़ी पर चढ़ गए। इसके बाद

कार्यकर्ता बेरीकेडिंग को पार करके आगे बढ़ गए। वारिस पंजाब दे के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहा किया जाए। गौरतलब हो कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें अजनाला थाने पर हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के उल्लंघन, और कई अन्य आपराधिक मामलों के तहत गिरफ्तार किया गया था। **अमृतपाल सिंह को कब किया गया था अरेस्ट-** अमृतपाल सिंह की 23 अप्रैल 2023 को पंजाब के मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तारी हुई थी। फरवरी 2023 में अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुए हिंसक हमले, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास में दबोचा।

नीतिश के वीडियो को एआई बताने पर भड़की जेडीयू

- नीरज कुमार ने पीके के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

पटना (एजेंसी)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के एक वीडियो को लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस वीडियो को जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने फर्जी और एआई जेनरेडेट बताया था।

इसके बाद जनता दल (यूनाइटेड) पूरी तरह आक्रामक हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के इस दावे को भ्रामक और साजिश करार देते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जेडीयू ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार का एक चुनावी अपील वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में वे जनता से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि यह वीडियो असली नहीं है, बल्कि इसे एआई तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से बनाया गया है।

गुरुजन जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं : प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट

महर्षि सांदीपनि पर्व एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उत्कृष्ट शिक्षकों, मेधावी विद्यार्थियों और नव नियुक्त शिक्षकों का सम्मान

ग्वालियर। मलगढ़ा स्थित सांदीपनि कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महर्षि सांदीपनि पर्व एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि गुरु ही जीवन को सही दिशा देकर उसे सफल और सार्थक बनाते हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेशभर के सांदीपनि विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाकर गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है।

कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षकों, बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा नव नियुक्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक मोहन सिंह राठौर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रियंका घुरैया, कलेक्टर रुचिका चौहान, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री सिलावट ने छात्राओं से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में मेहनत करने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सरकार विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि गुरु केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि संस्कार और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत एवं महर्षि सांदीपनि पर आधारित लघु नाटिका की प्रस्तुति दी। विज्ञान प्रदर्शनी में जल शोधन संयंत्र, एआई तकनीक, रॉकेट लॉन्चर और अन्य वैज्ञानिक मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। प्रभारी मंत्री सहित अन्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रभारी मंत्री सिलावट ने स्वयं गुरुजनों के पास जाकर शॉल, श्रीफल एवं पुष्पहार से उनका सम्मान किया तथा मंच पर अपना स्वागत नहीं कराया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने छात्राओं के साथ मध्यान्ह भोजन किया और विद्यालय परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

भोपाल में देसी घी के नाम पर बड़ा खेल, 10 क्विंटल घी जब्त, बिना लाइसेंस चल रहा था कारोबार

भोपाल। राजधानी में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मंगलवार को करोंद स्थित एक प्रतिष्ठान पर बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 10 क्विंटल (938 किलोग्राम) देसी घी जब्त किया। जब्त घी की अनुमानित कीमत 5.50 लाख बताई गई है। प्रारंभिक जांच में घी की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया है, जबकि प्रतिष्ठान बिना आवश्यक खाद्य लाइसेंस के संचालित होता मिला।

घी के बड़े भंडार पर प्रशासन का शिकंजा- खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने करोंद के पंचवटी कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठान पर छापा मारकर विभिन्न कंपनियों के 15 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम और 200 ग्राम पैक वाले देसी घी का बड़ा स्टॉक बरामद किया। संदेह के आधार पर पूरे स्टॉक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत जब्त कर लिया गया।

बिना लाइसेंस चल रहा था प्रतिष्ठान- जांच के दौरान अधिकारियों को प्रतिष्ठान पर अनिवार्य खाद्य लाइसेंस नहीं मिला और न ही लाइसेंस का प्रदर्शन किया गया था। इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए अलग से वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घी के नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। यदि जांच रिपोर्ट में घी तय मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान रहेगा जारी- खाद्य सुरक्षा प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

पीएम और सुरक्षाबलों को गाली देने वाले बचेंगे नहीं

- दिल्ली पुलिस भेज रही नोटिस, एक्स से भी मांगी अकाउंट होल्डर की पर्सनल डिटेल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऐक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस पीएम और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले सोशल मीडिया हैंडलों को नोटिस जारी कर रही है। इस

मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसके आधार पर एक्स से भी उन सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम और सुरक्षाबलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर इस शिकायत पर दर्ज की गई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवैधानिक प्रमुखों को टारगेट करके गलत, दुर्भावनापूर्ण और बदनाम करने वाला कंटेंट शेयर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि वह प्लेटफॉर्म से कथित पोस्ट या वीडियो तुरंत डिलीट कर दे। पुलिस ने हैंडल करने वालों का नाम भी पूछा है।

बारिश ने बिगाड़ी गुजरात-उत्तराखंड की सूरत

- छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 की मौत
- राजस्थान में बाजारों में पानी भरा, एमपी के बालाघाट में झमाझम

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद चार धाम यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में 12वीं तक के स्कूल-आंगनवाड़ी में छुट्टी कर दी गई है। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से बाजारों में पानी भर गया। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से टाटा मोटर्स के साणंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिट बंद करानी पड़ीं। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की तीन घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। राज्य में अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी है। **देश के ऊपर दो सिस्टम करा रहे जोरदार बारिश-** देश के ऊपर दो सिस्टम मौजूद हैं। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ रहा है। आईएमडी ने 4-5 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में मंगलवार को 50 मिमी से ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मानसूनी सिस्टम ने ये बारिश कराई। इसके चलते मेट्रो स्टेशन और कई सड़कों पर पानी भर गया, 36 पेड़ गिर गए। वाटरलॉगिंग की 136 शिकायतें दर्ज की गईं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन सब-डिवीजन में बुधवार को भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के चलते सभी सरकारी-निजी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि पहले से तय परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होंगी।

तीन घटनाओं में 5 लोगों की मौत

प्रदेश में बिजली गिरने की तीन घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। वहीं सारंगढ़ में नाले में बही कार में सवार पूर्व सरपंच और उनकी पत्नी का 60 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं, जहां 3.32 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और 45 हजार हेक्टेयर से अधिक फसल पानी में डूबी है।

- सीपीआई (एम) दफ्तर में पुलिस कार्रवाई को लेकर हुई तीखी बहस

राज्यसभा में भिड़े जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खरगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून सत्र के आज 8वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा में तीखी बहस हुई। खरगे ने सीपीआई (एम) के ऑफिस में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि अब देश में लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ ही विपक्ष लगातार 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर जेपी नड्डा ने खरगे के आरोपों पर पलवार करते हुए पुलिस कार्यवाही पर सरकार का बचाव किया। बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में घुसकर सीबीआई लोगों को उठा रही है। देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में एजेंसियां प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने मांग, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए।

खरगे के आरोपों पर नड्डा का पलटवार- खरगे के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, %पुलिस ने केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस के दौर में इससे बदतर दिन देखे हैं। छात्र जीवन के दौरान मैं भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका हैं। मुझे क्लासरूम से इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, कि विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।

तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ रुपए की जमीन हड़पी

- फर्जी दस्तावेजों के जरिए किया कब्जा, 19 लोगों पर एफआईआर

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर से जुड़ी एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 1.79 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला सामने आया है। इस जमीन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मदुरै सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और मॉर्गेज ट्रांजेक्शन से जमीन हथियाने की साजिश रची। यह कार्रवाई मंदिर के संयुक्त आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी सेल्लादुरई और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था अरापोर इयक्कम की शिकायत पर की गई है। **तहसीलदार पर लगा जमीन हड़पने का आरोप-** मामले में आरोप है कि 24 जून 2016 को तत्कालीन मदुरै उत्तर तहसीलदार अनबझगन ने सरकारी रिकॉर्ड से मंदिर का मालिकाना हक हटा दिया। उन्होंने अवैध रूप से जमीन का पट्टा 9 लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया था।

बुजुर्गों का सम्मान ही हमारी संस्कृति

इंदौर। बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति की आत्मा है और वह हमारी सांस्कृतिक चेतना का पवित्र सौपान भी है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह समाज अपनी जड़ों को काट रहा होता है। क्योंकि, हमारे बुजुर्ग संस्कारों के चलित विद्यालय होते हैं। इनके सम्मान और आशीर्वाद से हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मीयता का एहसास होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ये उद्गार डॉ अशोक कुमार भार्गव (आईएएस) पूर्व कमिश्नर रीवा एवं शहडोल संभाग ने श्री मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर के सभागृह में आयोजित वरिष्ठ नागरिक मंच के 35वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। डॉ भार्गव ने वरिष्ठ नागरिक मंच को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भीड़ में बुजुर्गों की आवाज दब जाती है किन्तु वरिष्ठ नागरिक जैसे मंच बुजुर्गों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। इन्हें तनाव और अकेलेपन से मुक्त कर इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मार्गदर्शक बनते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी रचनात्मकता को पुन: जाग्रत कर इनके अनुभव से समाज को लाभान्वित करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

बिना पर्ची गर्भपात की दवा बेची, दुकान सील

इंदौर। एमवाय हॉस्पिटल के सामने स्थित कार्तिक केमिस्ट पर थाना संयोगितागंज पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें गंभीर अनियमितता सामने आने पर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कार्तिक केमिस्ट द्वारा गर्भपात में उपयोग होने वाली दवा कॉन्ट्राकिट का बिना डॉक्टर की पर्ची के विक्रय किया जा रहा था। इसे औषधि नियमों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। मामले में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। औषधि विभाग के अनुसार नियंत्रक के निर्देश पर जिले में मेडिकल स्टोर्स की सघन जांच लगातार जारी है। अब तक 13 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 6 मेडिकल स्टोर पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं मिलने पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग का कहना है कि निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता, नार्कोटिक्स श्रेणी की दवाओं के रखरखाव और बिक्री तथा गर्भपात में उपयोग होने वाली औषधियों के विक्रय की विशेष रूप से जांच की जा रही है।

मासूम की मौत पर ठेकेदार के खिलाफ केस

इंदौर। शहर के बाणगंगा क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुए ई-रिक्शा चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, कनाड़िया इलाके में निर्माणाधीन मकान की खुली पानी की टंकी में डूबने से चार वर्षीय बच्चे ने दम तोड़ दिया। कनाड़िया थाना पुलिस ने चार वर्षीय रुद्र चौहान की मौत के मामले में निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार राजेश पवैया निवासी कुलकर्णी भट्टे के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि 10 जुलाई को संपत हिल्स स्थित निर्माणाधीन मकान के पास बनी खुली पानी की टंकी में गिरने से रुद्र की मौत हो गई थी। बच्चे के पिता गोलू चौहान और अन्य परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया गया कि घटना के समय गोलू काम पर गए थे, जबकि उनकी पत्नी पूजा घर पर दोनों बेटों कार्तिक और रुद्र के साथ थीं। खेलते-खेलते रुद्र निर्माणाधीन मकान के पास पहुंच गया और खुली पानी की टंकी में गिर गया। कुछ देर बाद परिजनों ने उसे बाहर निकालकर तत्काल सेवाकुंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क हादसे में रिक्शा चालक की मौत

इंदौर। बाणगंगा ब्रिज के पास 24 जुलाई को 38 वर्षीय कपिल रमण लाल निवासी पंचम की फेल ई-रिक्शा चला रहे थे। इसी दौरान सामने से आए वाहन को बचाने के प्रयास में उनका ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कपिल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें तत्काल एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बाद देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, कपिल ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और दो बच्चे हैं।

बात बंद करने पर प्रेमिका को पीटा

इंदौर। विवाद के चलते प्रेमिका को बात बंद करना महंगा पड़ गया। उसे प्रेमी ने बीच रोड़ पर रोका और बाल पकड़कर जमकर पीट दिया। यही नहीं, पेट पर लात मारी और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। जैसे-तैसे प्रेमिका वहां से भागी और राऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वह निजी कंपनी में नौकरी करती है। वह थाना क्षेत्र में रहने वाले शुभम को चार साल से जानती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शुभम की हरकतों के चलते उसने एक माह पहले बात करना बंद कर दिया। सोमवार को वह कंपनी जा रही थी। तभी रास्ते में शुभम पहुंचा और उसे पूछा कि वह बात क्यों नहीं करती। जब युवती आगे बढ़ने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और अपशब्द कहे। इसके बाद शुभम ने मारपीट की। इस दौरान आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो शुभम युवती को जान से मारने की धमकी दी।

परिवार विवाद, ठगी मामलों में कार्रवाई करें

इंदौर। आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें पुलिस कमिश्नर ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मामलों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान 89 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें सबसे अधिक शिकायतें पारिवारिक विवादों से जुड़ी रहीं। पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुना। कई मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए, जबकि कुछ मामलों में फोन पर बात कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निराकरण किया जाए।

पान की दुकान में डेढ़ लाख की चोरी

इंदौर। पुलिस की रात्रि गश्त को धता बताते हुए चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात चोरों ने एमजी रोड स्थित पान दुकान पर धावा बोलकर वहां से डेढ़ लाख की सिगरेट और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी केशर सिंह चौहान ने सेंट्रल कोतवाली पुलिस को बताया कि दुकान पहुंचने पर ताले टूटे मिले। अंदर रखे आईटीसी और मार्लबोरो कंपनी के 50 कार्टन सिगरेट, जिनकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए है और गल्ले में रखे पांच हजार रुपए नकद गायब थे। आरोपी पुलिस से बचने के लिए दुकान में लगा सीसीटीवी डीवीआर भी उखाड़कर ले गए। पुलिस आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

खजराना की बैंककर्मी युवती की मौत हादसा नहीं, निकली सुनियोजित हत्या

गैस रिसाव का नाटक रचा, शादी को लेकर विवाद के बाद हत्या

इंदौर। खजराना थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में जली हुई अवस्था में मिली 26 वर्षीय बैंककर्मी युवती की मौत के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस घटना को शुरुआत में गैस रिसाव से हुआ हादसा माना जा रहा था, वह जांच में सुनियोजित हत्या साबित हुई। पुलिस के अनुसार युवती की पहले गला घोंटकर हत्या की गई, फिर उसकी पहचान मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद कमरे में रखे एलपीजी सिलेंडर की नली निकाल दी गई, ताकि पूरा मामला गैस रिसाव से लगी आग का प्रतीत हो। पुलिस ने बताया कि मृतका पलक केशव (26) मूल रूप से हरदा जिले के टिमरनी की रहने वाली थी। वह इंदौर के तपेश्वरी बाग क्षेत्र में किराए के मकान में अकेली रहती थी और एक निजी बैंक में कार्यरत थी। घटना के बाद मौके की परिस्थितियों ने जांच अधिकारियों को संदेह में डाल दिया। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से जांच आगे बढ़ाई गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों ने पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दीं।

शादी को लेकर अक्सर विवाद

जांच में सामने आया कि वर्ष 2020 में पलक की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से दतिया जिले के डबरा निवासी मयंक से हुई थी। उस समय मयंक डबरा में रहता था, लेकिन बाद में काम के सिलसिले में इंदौर आ गया, जहां वह मोटर वाइंडिंग का काम करने लगा। इंदौर में एक शो के ऑडिशन के दौरान दोनों की फिर मुलाकात हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इसी विषय को लेकर उनके बीच अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन भी दोनों के बीच शादी को लेकर कहासुनी हुई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद के दौरान पलक ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे वह गुस्से में आ गया और उसने कथित रूप से पलक का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

हत्या को हादसा बताने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी ने पूरे मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक उसने शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर की नली निकाल दी, ताकि ऐसा लगे कि गैस रिसाव के कारण आग लगी और युवती की जान चली गई। इतना ही नहीं, आरोपी जले हुए कपड़े और अन्य सामान एक बैग में भरकर अपने साथ ले गया, जिससे वारदात से जुड़े साक्ष्य नष्ट किए जा सकें।

सीसीटीवी कैमरों में युवक दिखा

मामले की जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। इनमें एक युवक हाथ में पेट्रोल की केन लेकर आते और जाते हुए दिखाई दिया। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने तकनीकी जांच को आगे बढ़ाया। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के मिलान के बाद संदेह मयंक पर गया। पूछताछ में मिले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

हत्या का खुलासा ऐसे

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती स्थिति में मामला दुर्घटना जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन, फोरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हत्या का खुलासा हो गया। आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस इस मामले के अन्य पहलुओं की भी विस्तृत जांच कर रही है।

पदोन्नति का रास्ता 10 साल बाद खुला

कलेक्टर ने नए पदोन्नति नियम-2025 के तहत जारी किए आदेश

इंदौर। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को इंदौर में फिर से गति मिल गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के प्रावधानों के अनुसार 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 28 जुलाई से प्रभावी हो गया है। पदोन्नत सभी कर्मचारी फिलहाल अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही सहायक ग्रेड-3 के पद का कार्यभार संभालेंगे।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार यह पदोन्नति 27 जुलाई को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की गई है। हालांकि, यह पदोन्नति अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी-13954/2016) तथा उच्च न्यायालय में विचाराधीन संबंधित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। न्यायालय के अंतिम फैसले के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पदोन्नति से जुड़े आदेशों में संशोधन या अन्य कार्रवाई की जा सकेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नत कर्मचारियों को 2 वर्ष की परीक्षण अवधि पूरी करनी होगी। यदि इस दौरान किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच, लोकायुक्त में प्रकरण या किसी न्यायालय में मामला लंबित पाया जाता है अथवा उसकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं मिलती है, तो उसकी पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

9 को मिला सहायक ग्रेड-3 का दर्जा

इन्हें मिला पदोन्नति का लाभ

पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों में आनंद देलवार, सुरेंद्र कुमार पटेल, आनंद माली, पूजा गुप्ता, पूनम गौड़, जितेंद्र कुमार गौर, हरिओम डांगी, नेहा ठाकुर और अस्मिता सुखदेवे शामिल हैं। सभी कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स लेवल-4 के अंतर्गत रू. 19,500 से रू. 62,000 तक के वेतनमान का लाभ मिलेगा। कलेक्टर कार्यालय ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि वेतन निर्धारण, आरक्षण संबंधी प्रावधान तथा पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया राज्य शासन के निर्देशों और मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के अनुरूप लागू की गई है। इस निर्णय को लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 10 वर्षों से पदोन्नति की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से प्रभावित रही थी।

10 जोड़ी विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ी, इंदौर की दो सेवा भी जारी

अगस्त के अंत तक अलग-अलग तिथियों तक चलेंगी ट्रेनें

इंदौर। यात्रियों की लगातार बढ़ती आवाजाही और यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने विशेष किराये पर संचालित 10 जोड़ी विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है। इस निर्णय से इंदौर सहित पश्चिम रेलवे के विभिन्न मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। विस्तारित सेवाओं में इंदौर से मुंबई सेंट्रल और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें भी शामिल हैं। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मुंबई सेंट्रल-इंदौर विशेष ट्रेन संख्या 09085 अब 28 अगस्त, 2026 तक तथा वापसी में ट्रेन संख्या 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल विशेष 29 अगस्त तक संचालित होगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09079 मुंबई सेंट्रल-इंदौर विशेष 30 अगस्त तक और ट्रेन संख्या 09080 इंदौर-मुंबई सेंट्रल विशेष 31 अगस्त तक चलेगी। इंदौर से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 09309 विशेष सेवा का संचालन 30 अगस्त तक किया जाएगा, जबकि वापसी में ट्रेन संख्या 09310 हजरत निजामुद्दीन-इंदौर विशेष 31 अगस्त तक यात्रियों को उपलब्ध रहेगी।

अन्य ट्रेनों की अवधि भी बढ़ी - रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली अन्य विशेष ट्रेनों की अवधि भी बढ़ाई गई है। ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस-भिवानी विशेष 26 अगस्त, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09006 भिवानी-बांद्रा टर्मिनस विशेष 27 अगस्त तक संचालित होगी। वहीं ट्रेन संख्या 09001 मुंबई सेंट्रल-भिवानी विशेष 28 अगस्त, 2026 तक और ट्रेन संख्या 09002 भिवानी-मुंबई सेंट्रल विशेष 29 अगस्त तक चलेगी। मुंबई सेंट्रल और कानपुर अनवरगंज के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 09185 विशेष 30 अगस्त तक तथा वापसी में ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल विशेष 31 अगस्त, 2026 तक संचालित रहेगी। अहमदाबाद-पटना विशेष ट्रेन संख्या 09447 का संचालन 5 अगस्त, 2026 तक और वापसी में ट्रेन संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद विशेष 7 अगस्त तक जारी रहेगा।

उधना-अयोध्या भी बढ़ाई गई - उधना-अयोध्या कैंट मार्ग पर चलने वाली दो जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरों का भी विस्तार किया गया है। ट्रेन संख्या 09093 उधना-अयोध्या कैंट विशेष 28 अगस्त तक तथा ट्रेन संख्या 09094 अयोध्या कैंट-उधना विशेष 29 अगस्त तक चलेगी। इसी मार्ग पर दूसरी विशेष सेवा ट्रेन संख्या 09097 उधना-अयोध्या कैंट 25 अगस्त तक तथा ट्रेन संख्या 09098 अयोध्या कैंट-उधना विशेष 26 अगस्त तक संचालित होगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम-भागलपुर विशेष 28 अगस्त तक तथा वापसी में ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर-गांधीधाम विशेष 31 अगस्त तक यात्रियों की सेवा में उपलब्ध रहेगी।

फर्जी ट्रैवल पैकेज के झांसे में आए वकील से डेढ़ लाख ठगे, केस दर्ज

दक्षिण भारत की यात्रा के नाम पर एडवांस, टिकट नहीं भेजे

इंदौर। वकील से ऑनलाइन ट्रैवल पैकेज के नाम पर डेढ़ लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपियों ने अखबार में प्रकाशित ट्रैवल पैकेज के पम्पलेट के जरिए संपर्क किया। इसके बाद दक्षिण भारत की यात्रा का आकर्षक पैकेज भेजकर एडवांस राशि जमा करवा ली। रकम लेने के बाद न टिकट दिए और न पैसे लौटाए। एमजी रोड थाना पुलिस के अनुसार, फरियादी राकेश लाड ने बताया कि 15 दिन पहले अखबार में 'स्वास्तिक टूर' के नाम से यात्रा पैकेज का पम्पलेट मिला था। पम्पलेट पर दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर प्रवीण घोडके नामक युवक ने व्हाट्सएप पर दक्षिण भारत यात्रा का पैकेज भेजा। मैंने वाराणसी, अयोध्या, रामेश्वरम समेत अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए अलग पैकेज की मांग की। इसके बाद 16 जुलाई को चार लोगों के लिए 2.34 लाख रुपए का टूर पैकेज भेजा गया। आरोपियों ने कुल राशि का 60 प्रतिशत एडवांस जमा कराने की शर्त रखी और भुगतान के लिए क्यूआर कोड भेज दिया।

टिकट नहीं भेजे न पैसे लौटाए - रकम मिलने के बाद आरोपियों ने 24 घंटे के भीतर टिकट भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन तय समय पर टिकट जारी नहीं किया। जब मैंने संपर्क किया तो आरोपी लगातार अलग-अलग बहाने बनाकर तारीख टालते रहे। बाद में जब उन्होंने अपनी राशि वापस मांगी तो आरोपियों ने खाते में प्रतीकात्मक रूप से एक रुपया ट्रांसफर कर भरोसा दिलाया कि बाकी रकम आरटीजीएस के जरिए लौटा दी जाएगी। लेकिन, न पैसे वापस किए गए और न टिकट उपलब्ध कराए गए। धोखाधड़ी का एहसास होने पर मैंने 24 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई।

आबादी में हाथी के आने पर आपत्ति, हादसा होने के बाद प्रशासन जागा

धार्मिक आयोजन में लाया गया था हाथी, अनुमति की जांच होगी

इंदौर। चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर में हाथी के हमले में ऑटो रिक्शा चालक की मौत के बाद पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर हाथी जैसे विशालकाय वन्यजीव को बिना पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों के शहर की घनी आबादी वाले इलाके में कैसे लाया गया। घटना के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का निर्णय लिया है।

जानकारी के अनुसार राजनगर क्षेत्र में एक धार्मिक आयोजन के लिए हाथी लाया गया था। इसी दौरान स्थानीय ऑटो चालक हाथी को गुड़-चना खिलाने पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही वह

हाथी के करीब पहुंचा, हाथी अचानक आक्रामक हो गया। उसने युवक को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर कुचल दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह युवक को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने महावत से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि हाथी को शहर में लाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमति ली गई थी या नहीं, सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं तथा आयोजन स्थल पर भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे या नहीं। इंदौर कलेक्टर ने कहा कि शहर की सीमा में हाथी जैसे बड़े जानवरों के प्रवेश को लेकर मौजूदा नियमों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए विस्तृत एसओपी तैयार की जाएगी, जिसमें अनुमति प्रक्रिया, सुरक्षा घेरा, प्रशिक्षित महावत की मौजूदगी, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्था जैसे सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद भविष्य में धार्मिक आयोजनों या अन्य कार्यक्रमों में बड़े जानवरों को लाने से पहले कड़े सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाएगा।

फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाली गैंग का पदार्फाश, कई प्रमाण मिले

तीन गिरफ्तार, करोड़ों रूपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ

इंदौर। शेयर ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ और बैंक खातों की तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ठगी से जुटाए पैसे को ठिकाने लगाने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। पुलिस को बैंक खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन के प्रमाण भी मिले हैं। थाना परदेशीपुरा में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई ठगी के मामले में आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पूर्व में गिरफ्तार आरोपी जय सूर्यवंशी और जतिन हरियाले से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण में गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका सामने आई। इसी आधार पर पुलिस ने आकाश पिता राधेश्याम विश्वकर्मा निवासी प्रीमियम पार्क, अरविंदो हॉस्पिटल के सामने, प्रवीण पिता छोटेलाल पाल निवासी शिवकंठ नगर, सांवेर रोड तथा आशीष पिता अशोक पुरी निवासी स्कीम नंबर-51, आईडीए बिल्डिंग, ब्लॉक-बी को गिरफ्तार किया है।

15 मोबाइल, बैंक दस्तावेज जब्त

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल, विभिन्न बैंकों की पासबुक, सिम कार्ड, बैंकिंग से जुड़े अहम दस्तावेज और स्कॉर्पियो कार जब्त की गई है। पुलिस इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ठगी करने वाले गिरोह के संपर्क में थे। उनका काम अलग-अलग लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाना, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक व सिम गिरोह तक पहुंचाना था। इन्हीं खातों का इस्तेमाल शेयर ट्रेडिंग, निवेश और अन्य फ्रॉड से हासिल की गई रकम को जमा करने, एक खाते से दूसरे खाते में भेजने और आगे वितरित करने का काम किया जाता था।

कई फ्रॉड मामलों से जुड़े

जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों का इस्तेमाल देश के कई राज्यों में दर्ज ठगी के मामलों में किया गया है। बैंक खातों के विस्तृत विश्लेषण में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है। पुलिस अब गिरोह के मास्टरमाइंड, बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले अन्य सहयोगियों और ठगी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। आरोपियों की संपत्ति संबंधी जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसके लिए संबंधित नगर निगम से जानकारी मांगी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर आगे भी गिरफ्तारी की जाएगी।

डाक कर्मचारियों का प्रदर्शन, 5 को हड़ताल

इंदौर। डाक विभाग के निजीकरण के विरोध और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा को लेकर भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को देशभर में चरणबद्ध आंदोलन के तहत संभागीय कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। इंदौर में भी कर्मचारियों ने लंच अवकाश के दौरान प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की तथा अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। महासंघ के संभागीय सचिव प्रेम रावत ने बताया कि इंदौर सहित देशभर के सभी संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ प्रदर्शन किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान नहीं कर रहा है और डाक विभाग के निजीकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदम कर्मचारियों के हितों के विपरीत हैं। 5 अगस्त को देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

संपादकीय

पीओके में खूनी चुनाव

पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (पीओके) में विधानसभा चुनाव के नाम पर जो खुला खूनी खेल और जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए। क्योंकि इस चुनाव की कोई वैधता नहीं है। इस चुनाव में पाक फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए 30 लोगों की हत्या करने में भी परहेज नहीं किया। इसके अलावा मतदान में भी जबर्दस्त धांधली की। पीओके के लोगों ने इस चुनाव का पहले ही बहिष्कार कर दिया था। इसके बावजूद जोर जबर्दस्ती के कुछ वोट डलवाए गए। मंगलवार को पाकिस्तानी चुनाव आयोग की तरफ से जारी अनौपचारिक नतीजों के अनुसार पीओके में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। पार्टी ने मीरपुर डिवीजन की 13 में से नौ सीटों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान के 'डॉन' अखबार के मुताबिक फ़ॉर्म-26 और फ़ॉर्म-27 पर आधारित शुरुआती नतीजों में PML-N अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) से काफी आगे रही। PPP सिर्फ चार सीटें ही जीत सकी। पीपीपी ने इन चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। गौरतलब है कि पीओके में भारी सुरक्षा के बीच तीन चरणों वाले चुनाव के तहत सोमवार को वोटिंग हुई थी। पहला चरण मारपीट, हिंसा और चुनाव में धांधली के आरोपों से प्रभावित रहा। PML-N और PPP ने वोटिंग के दौरान एक-दूसरे पर चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए जिससे इस प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। स्थानीय लोगों के भारी विरोध से बौखलाए मुनीर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने में कोताही नहीं की। पाक रेंजरों ने तीस लाशें बिछा दीं। मरने वालों का दोष यही था कि वो पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे थे और आजादी की मांग कर रहे थे। वहां ये विरोध-प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, प्रशासन से जुड़ी समस्याओं और सब्सिडी वाले गेहूं के आटे और बिजली की मांग को लेकर हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अदालत के उस फ़ैसले का भी विरोध किया था जिसमें पाकिस्तान में बसे प्रवासियों के लिए विधानसभा की 12 सीटें आरक्षित रखने को सही ठहराया गया था। ये वो सीटें हैं, जो भारत के जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान गए लोगों और पीओके के उन लोगों के लिए आरक्षित हैं, जो पीओके छोड़कर पाकिस्तान में अन्यत्र बस गए हैं। पाक सरकार इन्हीं सीटों के बल पर अपना खेल करती है, क्योंकि इन सीटों पर जीतने वाले सरकार के पिट्ठू ही होते हैं। कहने को पीओके को पाक सरकार 'आजाद कश्मीर' कहती है, लेकिन वास्तव में वो पाक सरकार का गुलाम कश्मीर है, जहां के निवासी गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। ये लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन कश्मीर को अपना कोर मुद्दा मानने वाली पाक सरकार उसे किसी तरह पकड़े रखना चाहती है ताकि भारत के लड़ने का एक मुद्दा हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सके। उधर भारत के हिस्से वाले कश्मीर के विकास की कहानियां भी पीओके पहुंचती रहती हैं। ऐसे में उन्हें लगने लगा है कि उन्हें भारत के साथ रहना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अभी वो पाक से आजादी तथा एलओसी को खोलने की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन कर रहे हैं। पीओके के हालात इतने खराब हैं कि पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जल्द ही पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह में हालत पहले से खराब हैं। पाक सरकार फौज के बलबूते पर देश को एक बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। लेकिन लोगों का गुस्सा भड़कता ही जा रहा है। पीओके में निर्दोषों की हत्या से पाक सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है।

नजरिया

तनवीर जाफ़री

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ट्रंप की नीतियों ने गिराई अमेरिका की साख

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही अमेरिका को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में वैश्विक मान्यता मिल चुकी थी। तब तक अमेरिका परमाणु बम सम्पन्न देश होने के अलावा संयुक्त राष्ट्र के गठन में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाने लगा था। साथ ही अमेरिकी डॉलर ने भी अपनी वैश्विक भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी। हालांकि 1945 के बाद ही सोवियत संघ को भी विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा था परन्तु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद तो अमेरिका अकेली वैश्विक महाशक्ति रह गया। उसी समय से 'विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति' के रूप में अमेरिका की स्वीकार्यता लगभग निर्विवाद हो गई थी। उसके बाद अमेरिका स्वयं को वैश्विक महाशक्ति के साथ-साथ 'वैश्विक थानेदार' के रूप में भी स्वयं को देखने लगा। और लगभग विश्व के सभी देशों के आंतरिक मामलों पर नज़र रखने लगा। धीरे धीरे प्रत्येक दो पड़ोसी देशों के आपसी मतभेदों,तनाव अथवा सीमा विवाद का लाभ उठाकर अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने व अमेरिकी सैनिकों की तैनाती करनी शुरू कर दी। एक अनुमान के अनुसार इस समय विश्व भर में अमेरिका के लगभग 750 से अधिक सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ये अड्डे लगभग 80 अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। इनमें स्थायी बेस, एयरबेस, नौसैनिक अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर और छोटे 'लिली पैड' फ़ारवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन आदि शामिल हैं। पेंटागन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 के आसपास क़रीब 1,08,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक लगभग 160 देशों में तैनात या अग्रिम रूप से मौजूद हैं। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती सैन्य अड्डों से कहीं अधिक देशों में फैली हुई है। जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की गिनती उन देशों में हैं जहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डों और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती सबसे अधिक है।

दूसरी तरफ़ 1970-80 के दशक में चीन की 'भविष्य की महाशक्ति' के रूप में कल्पना की जाने लगी। और 1990-2000 के दशकआते आते उसे एक 'उदयमान महाशक्ति' के रूप में देखा जाने लगा। और 2010 के बाद से तो चीन को व्यावहारिक रूप से अमेरिका के बराबर या उसके बाद आने वाली वास्तविक वैश्विक महाशक्ति के रूप में गिना जाने लगा। गोया चार दशकों पहले तक जो चीन, दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में गिना जाता था वही देश 1978 के बाद के सुधारों से तेज़ी से बढ़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और आज वैश्विक उत्पादन व सप्लाई चेन में उसकी केंद्रीय भूमिका है। बड़े पैमाने पर निर्माण, निर्यात-आधारित विकास, विदेशी निवेश के लिए खुले विशेष आर्थिक क्षेत्र, और कम लागत वाली श्रमशक्ति ने चीन को विश्व अर्थव्यवस्था की धुरी बना दिया। इसी अवधि में चीन

ने अपनी सेना को आधुनिक बनाया, नौसेना, मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारी निवेश किया, जिससे उसे केवल विश्व की आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक महाशक्ति के रूप में भी देखा जाने लगा। 5त्र, एआई, अंतरिक्ष प्रक्षेपण और हाई-टेक विनिर्माण में उसकी तेज़ प्रगति ने 'मेड इन चाइना 2025' जैसी रणनीतियों के तहत तकनीकी महाशक्ति की छवि को भी विश्व स्तर पर मज़बूत किया। बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से एशिया, अफ़्रीका और यूरोप में आधारभूत संरचना पर निवेश व ऋण देकर चीन ने अपनी भू-राजनीतिक पकड़ और कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाया, जो महाशक्ति का एक प्रमुख गुण माना जाता है। साथ ही ताइवान, दक्षिण चीन सागर और सीमा विवादों पर उसकी मुखर नीति ने भी यह संदेश दिया कि वह क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के स्तर पर 'खेलना' चाहता है। परन्तु अमेरिका व चीन की वैश्विक नीतियों में यह बड़ा अंतर भी रहा कि चीन ने अमेरिका की तरह दूसरे देशों से 'थानेदार' जैसा बर्ताव करने के बजाये क्षेत्रीय मामलों में ग़ैर ज़रूरी दख़लअंदाज़ी से परहेज़ किया। दूसरे देशों की प्राकृतिक सम्पदाओं पर गिद्ध दृष्टि नहीं रखी। दो देशों को, आपस में लड़ाकर अपने हथियार बेचना,किसी देश पर क़ब्ज़ा कर लेना, धमकाना या किसी राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण कर लेना जैसी छिछोरी नीति नहीं अपनाई।

चीन और शी ज़िननपिंग तथा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों का परिणाम पिछले दिनों अमेरिकी रिसर्च संस्था Pe2 शोध केंद्र के ताज़ातरीन वैश्विक सर्वे में परिलक्षित होकर सामने आया है। इस सर्वे में यह पाया गया कि अमेरिका के मुक़ाबले चीन की और ट्रंप के मुक़ाबले शी ज़िनपिंग की विश्व में लोकप्रियता व उनके प्रति विश्व में भरोसा बढ़ा है। अमेरिकी रिसर्च संस्था द्वारा यह सर्वे पिछले दिनों 36 देशों में किया गया। सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार 36 में से लगभग 25 देशों में लोगों ने चीन के प्रति अमेरिका की तुलना में अधिक सकारात्मक राय व्यक्त की। इसी सर्वे में विश्व मामलों को संभालने की क्षमता व विश्वसनीयता के मामले में शी ज़िनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप से अधिक विश्वास मिला। इस सर्वे में पहली बार यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से नज़र आई कि कई देशों में चीन की छवि अमेरिका से अधिक सकारात्मक हो गई है, जबकि पिछले दो दशकों में आमतौर पर अमेरिका की छवि चीन से बेहतर रहती थी। 27 देशों में लोगों ने चीन को अमेरिका से अधिक अनुकूल रूप में देखा। यानी चीन को बेहतर सहभागी, निवेशक और स्थिर शक्ति माना। कई देशों में लोगों ने अंतरराष्ट्रीय मामलों को संभालने की क्षमता के मामले में भी शी ज़िनपिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में अधिक भरोसा जताया। आश्चर्य तो यह है कि जिन 36 में से लगभग 22 देशों में लोगों ने शी जिनपिंग को ट्रंप से बेहतर या अधिक पसंदीदा नेता माना इनमें कनाडा, मैक्सिको, फ़्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे महत्वपूर्ण पश्चिमी देश भी शामिल हैं। ट्रंप के नेतृत्व पर भरोसा कई देशों में बहुत कम रहा। एक पुराने वैश्विक सर्वे में भी 70% उत्तरदाताओं ने ट्रंप पर अंतरराष्ट्रीय मामलों में भरोसा नहीं जताया था जो कि उनके प्रति लंबे समय से चली आ रही 'शंकाओं' को दिखाता है। कई विकासशील देशों को यह भी लगता है कि चीन उन्हें सड़कों, बंदरगाहों, उद्योग और डिजिटल आधारभूत संरचना में तत्काल मदद दे रहा है, जबकि अमेरिका की मदद प्रायः राजनीतिक शर्तों पर आधारित तथा सुरक्षा गठबंधनों से बंधी हुई होती है। चीन ने एशिया, अफ़्रीक़ा, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में आधारभूत संरचना में निवेश, लोन, बेल्ट ऐंड रोड जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए 'विकास साझेदार' की छवि बनाई है, जिससे वहाँ के आम लोगों में चीन को अवसर देने वाली शक्ति के रूप में देखा गया। इसी सर्वेक्षण और इसके विश्लेषणों में खुलकर कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान कई फ़ैसलों ने अमेरिकी छवि को काफ़ी नुक़सान पहुँचाया है। जैसे सहयोगी देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध, विदेशी सहायता में कटौती, कठोर व्यापार विवाद और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दूरी,ट्रंप की बोल भाषा, मुस्लिम देशों, आप्रवासियों और सहयोगियों के प्रति उनके विवादित बयान, NATO, यूरोपीय यूनियन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर बार-बार हमले जैसे कारकों ने उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर भी व उनके साथ ही अमेरिका के प्रति भी दुनिया का भरोसा कम किया है। रही सही कसर ईरान-इस्राईल, मध्य पूर्व,वेनेज़ुएला व यूक्रेन आदि के प्रति ट्रंप की नीतियों ने पूरी कर दी। कहना ग़लत नहीं होगा कि ट्रंप की नीतियां ही विश्व में अमेरिका की साख गिरने की ज़िम्मेदार हैं।

न्यायिक सुधार

राजेश कुमार चौधरी

(लेखक एवं स्तंभकार)

सिविल और आपराधिक मामलों के लिए अलग कोर्ट हो

न्याय प्रक्रिया में विलंब दर्शाता है, कि देश की न्याय प्रक्रिया अब भी पारम्परिक ढर्रे पर चल रही है। तकनीकी सुख सुविधाओं को न्यायालयों ने पूरे मनोयोग से नहीं अपनाया। अन्यथा विद्युत गति से सूचना और संदेश के इस युग में न्याय पूर्ण करने में इतना विलंब नहीं होता। न्याय के विलम्ब से देश के न्यायालयों में लंबित मुकदमों का अम्बार बढ़ रहा है। रोज सैकड़ों प्रकरण दायर होते हैं। किन्तु , उनमें से एक चौथाई प्रकरणों का निराकरण भी शीघ्रता से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कुछ सुधार किया जाना जरूरी है। जैसे सिविल और आपराधिक मामलों के लिए अलग न्यायालय होना।

हमारे देश में देर से मिलने वाले न्याय के कारण न्यायपालिका के प्रति लोगों में विरोध है। सिविल प्रकरण हो या आपराधिक प्रकरण, सभी में न्याय मिलने में देरी होती है। देश के जो लोग न्याय की उम्मीद में न्यायालयों में जाते हैं। उन्हें न्याय के मंदिर में प्रवेश तो मिल जाता है, किंतु उन्हें अपनी फरियाद पर कब न्याय मिलेगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। न्याय की यह अनिश्चितता ही न्याय प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर प्रश्न खड़े करती है। क्या यह नहीं हो सकता है कि जिस दिन प्रकरण न्यायालय आए और उसकी सुनवाई प्रारंभ हो, उसी दिन प्रकरण पर निपटान की संभावित अवधि भी अंकित कर दी जाए।

वर्तमान समय तेज गति का युग है। जीवन के हर क्षेत्र में तकनीकी सुविधाएं सुलभ हैं। देश में सूचना, संदेश और आवागमन आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ है। इस सुगम विकास के बाद भी न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। सिविल प्रकरण हो या आपराधिक प्रकरण। सभी प्रकरणों में वांछित साक्ष्य अब पुख्ता स्वरूप में उपलब्ध हो सकते हैं। गवाहों को सूचना और उनकी उपस्थिति में भी अब पहले की तरह कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि, सूचना और संदेश के साधन सुगम हैं तथा आवागमन के साधन भी देश में सहजता से उपलब्ध है। आवागमन के साधनों के मामले में देश बैलगाड़ी युग से बहुत आगे आ चुका है। पांच-छह दशक पहले का वह समय अब नहीं रहा, जब साक्ष्य प्रस्तुत करने में बहुत विलंब होता था। आवागमन के सीमित साधनों के कारण पक्षकारों और गवाहों को न्यायालय तक पहुंचने में बहुत देर लगती थी। अब सभी कुछ सहज और सरल रूप से उपलब्ध है।

देश की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ, देश के लोगों में एक नयी उम्मीद जागी थी कि उन्हें अपने प्रकरण के निराकरण या अपील और अंतिम निर्णय के लिए सुदूर लंदन की प्रिवी काउंसिल तक छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बल्कि, उन्हें सुलभ और शीघ्र न्याय देश में ही उपलब्ध होगा। इसके लिए देश में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिलों में सत्र न्यायालय और तहसीलों तक में न्यायालय की श्रृंखला निर्धारित की गई थी। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, न्यायालयों का यही पारम्परिक रूप नहीं, अपितु राजस्व न्यायालय, विभिन्न प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सीमा, उत्पाद शुल्क विवाद के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, औद्योगिक विवाद हेतु पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण, आयकर विवाद न्यायाधिकरण, उपभोक्ता न्यायालय आदि पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि लगभग बीस से अधिक विभिन्न प्रकार के न्यायालय गठित हो चुके हैं।

देश के विभिन्न न्यायालयों में वर्तमान में लगभग 5 करोड़ से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इन लंबित प्रकरणों में से एक करोड़ से अधिक मामले केवल सिविल प्रकरणों से संबंधित हैं। सिविल प्रकरणों में बड़ा हिस्सा भूमि, मकान सम्पत्ति और पारिवारिक मामलों से जुड़ा हुआ है। शेष 70 से 80 प्रतिशत प्रकरण आपराधिक (क्रिमिनल) प्रकृति के हैं। देश की वर्तमान जनसंख्या 140 करोड़ अनुमानित है। इस वृहद जनसंख्या पर

दृष्टिपात करें तो देश का हर चौदहवां व्यक्ति सिविल विवाद में न्यायालयों के चक्कर लगा रहा है। आपराधिक प्रकरणों की स्थिति तो और भी चौंकाने वाली है। लंबित मुकदमों की संख्या के अनुपात में हर आठवां व्यक्ति आपराधिक प्रकरण लड़ रहा है।

देश की स्वतंत्रता को आठ दशक पूरे होने को हैं। देश में संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू हुए भी पौन सदी बीत चुकी है। किन्तु, देश में आपराधिक प्रकरणों में कमी लाने के प्रयासों का नीतिगत अभाव है। जिस मात्रा में देश में आपराधिक प्रकरण लंबित है, उस पर विचार करें, तो देश का हर चौथा व्यक्ति आपराधिक स्वभाव का प्रतीत होता है। आपराधिक श्रेणी के ये प्रकरण नीतिगत स्तर पर देश की बहुत अच्छी छवि प्रदर्शित नहीं करते हैं। लोक मानस को सुधारने के लिए देश में शैक्षणिक संस्थानों का एक बड़ा साम्राज्य है। आध्यात्मिक स्तर पर भी नीतिगत ज्ञान के प्रचार-प्रसार की कोई कमी नहीं है। किन्तु, इन सबके बाद भी देश के न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों का तीव्रता से बढ़ना सारे नीतिगत प्रयासों को निरर्थक साबित कर रहा है। देश के अखबारों पर दृष्टि डालें तो रोज ही अपराधों के समाचार बहुतायत में पढ़ने को मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि देश की न्यायपालिका विभिन्न विवादित प्रकरणों के बोझ से दबी जा रही है।

देश में उच्चतम न्यायालय से लेकर जिला स्तर पर सत्र न्यायालय तक वर्तमान में सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरणों के निपटारे के लिए एक ही न्यायालय है। अत्यधिक मुकदमों की संख्या को दृष्टिगत कर क्यों न जिला स्तर पर गठित न्यायालयों को सिविल और आपराधिक (क्रिमिनल) न्यायालय के रूप में दो भागों में विभक्त कर दिया जाए। इसका एक लाभ यह होगा कि एक ही न्यायालय में लगने वाली भीड़ को विभाजित किया जा सकेगा। दूसरे सिविल और आपराधिक प्रकरणों में सिविल या आपराधिक विशेषज्ञता के साथ न्यायाधीश प्रकरणों पर विचार त्वरित गति से कर सकेंगे। इससे प्रकरणों के निराकरण को भी गति मिलेगी। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जो न्यायाधीश आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई करते हैं, वे ही सिविल प्रकरणों पर भी विचार करते हैं। इससे न्याय में विलम्ब होता है। यही कारण है कि देश की न्यायपालिका विलम्ब से न्याय कारण अपनी ख्याति दिन प्रतिदिन खोती जा रही है। अतः देश की वृहद जनसंख्या और विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को देखते हुए सिविल और न आपराधिक प्रकरणों की शीघ्र एवं पृथक पृथक सुनवाई के लिए विभाजन समय की मांग है।

रोज 42 लोग कर रहे हैं आत्महत्या

कैग रिपोर्ट

संदीप कुलश्रेष्ठ

लेखक स्तंभकार हैं।

हाल ही में कैग ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में रोज 42 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय औसत 10.6 है। इस प्रकार प्रदेश में आत्महत्या करने वाले लोग राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। यह चिंताजनक है। किन्तु इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि आत्महत्या करने वालों में 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों की दर 24.55 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय औसत 17.1 प्रतिशत ही है।

आत्महत्या के कारण

कैग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या का कारण यह है कि प्रदेश में 13.9 प्रतिशत लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। अर्थात 1.01 करोड़ से भी ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी के शिकार हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रदेश में न तो पर्याप्त बेहतर इलाज है और न ही पर्याप्त काउंसलिंग की व्यवस्था। आत्महत्या के अन्य कारणों में प्रमुख कारण कैरियर की समस्याएँ, एकाकीपन, दुर्व्यवहार, पारिवारिक कलह, हिंसा, मानसिक तनाव, शराब या अन्य नशे की लत, दीर्घकालीन गंभीर बीमारी आदि हैं।

मानसिक बीमारी के ईलाज का अभाव

कैग ने इतने सारे लोगों में मानसिक बीमारी के शिकार होने को एक बड़ी समस्या बताते हुए बताया कि इसके प्रमुख कारणों में यह है कि प्रदेश में 1 लाख लोगों पर 0.05 मनोचिकित्सक ही हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रति 1 लाख लोगों पर 3 चिकित्सक होना चाहिए। इसी प्रकार जिला अस्पताल और सीएचसी में जरूरी 23 में से 15 दवाएं है ही नहीं। यही नहीं जाँच के लिए 47 से 100 प्रतिशत उपकरण भी नहीं है। इन्दौर और ग्वालियर में सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस के लिए 10 करोड़ रूपए राज्य शासन द्वारा दिए गए, किन्तु उसका उपयोग भी वे नहीं कर सके। मानसिक बीमारी की जाँच के लिए चयनित अस्पतालों में 480 पद स्वीकृत है। इनमें से 267 ही भरे हुए है। यहाँ 45 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।

कुछ हुई ऐसी भी लापरवाही

इंदौर और भोपाल में स्थापित काउंसलिंग सेन्टर में पिछले 2 साल में आए 85,260 कॉल में से 9,855 कॉल का उत्तर ही नहीं दिया गया। यहीं नहीं इसके लिए बनाए गए अस्पतालों से 409 मरीज भाग गए। वे वापस नहीं लाए गए। उनका फॉलोअप भी नहीं किया गया।

गंभीर प्रयास की जरूरत

कैग की रिपोर्ट को राज्य शासन द्वारा गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। प्रदेश में हो रहे आत्महत्या के कारणों का विश्लेषण करते हुए उसके निदान के ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों की काउंसलिंग और ईलाज की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा युवाओं द्वारा आत्महत्या नहीं की जाए इसके लिए उनके माता पिता और अन्य अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्हें युवाओं से आत्मीय व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि वे समय पर अपनी समस्या उन्हें बता सके और उसका समय पर निदान होने से वे आत्महत्या से बच सकेंगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वक्रोक्ति

मुकेश नेमा

लेखक मप्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं।

एडिशनल कमिश्नर होते ही बंदा ज्यादा आदरणीय हो जाता है

एडिशनल की कुर्सी पर काबिज हुए नौ साल बीत गये अब तो। पर बनने के पहले मुझे हरगिज पता नहीं था कि एडिशनल कमिश्नर होते ही बंदा इतना ज्यादा आदरणीय हो जाता है। पता होता तो मैं और पहले हो जाने की कोशिश करता। वैसे एडिशनल होकर आदरणीय होने के फायदे भी है और नुकसान भी। सबसे बड़ा नुकसान तो यह कि खुद को बुजुर्ग महसूस करने लगते है आप। बहुत से ऐसे ज़रूरी काम करने में संकोच होने लगता है जो करने का मन तो बहुत होता है पर एडिशनल होना उसे रोकता है। नुक़सानों की लिस्ट बड़ी लंबी है। पर नुकसान की बाते करके मन खराब क्यों किया जाए, इसलिये इसके फायदे गिनना ही बेहतर है।

सबसे पहला और बडा फायदा यह कि आपको अकलमंद मान लिया जाता है। मन ही मन ना भी मानें पर आपके सामने तो आपको अक्लमंद मानना मजबूरी हो जाती है लोगों की। आप कुछ भी कहें लोग मान लेते हैं कि बात गहरी ही होगी। लोग ध्यान से सुनने लगते है आपकी बात। बहुत बार उसके इतने गहरे मतलब निकाल लिये जाते है कि आप खुद की कही पर हैरान होने लगते है। अक्लमंद समझा जाना सबको पसंद होता है, मुझे भी है इस मायने में एडिशनल होना अच्छा ही है।

एडिशनल होना वजनदार हो जाना है। वेट मशीन के साथ साथ अब आपकी कुर्सी भी इसकी तस्दीक करती है। कुर्सी बड़ी होते ही आपका कमरा बड़ा हो जाता है यह तो होता ही है, सवारी के लिये बड़ी कार मिलने की गुंजाईश आपको खुश कर देती है। हाँ में हाँ मिलाने के लिये कुछेक बाबू, चपरासी और जूनियर अफ़सर और मिल जाते हैं आपको, ये एडिशनल होने के अपने एडिशनल फायदे हैं। आपसे हाय करके मिलने वाले गायब हो जाते हैं। नमस्ते करने वाले भी कम हो जाते हैं और चरण स्पर्श करने वालों की तादाद अचानक बढ़ जाती है। आशीर्वाद देने योग्य मान लिया जाना,काम का होने लायक मानना जैसा है! इसलिये मैं इसे अपर होने के फायदों में शामिल करता हूँ।

बड़े अफ़सर आपसे सलाह लेने लगते हैं! इसलिये लेने लगते हैं कि सलाह लेने का क़ायदा ही यही है। और एडिशनल से सलाह भी ना लें तो उसका करें क्या? एडिशनल का काम ही सलाह देने का है। वो सलाह माँगे जाने का इंतज़ार करता है। मौक़ा मिलते ही फ़ौरन सलाह देता है। यह जानते बूझते देता है कि उसकी सलाह की कद्र किये जाने की गुंजाइश बहुत कम है।

तनख्वाह तो बढ़ती ही है एडिशनल होने से। कहीं आने जाने पर आपको लेने और छोडने आने वालो की गिनती भी बढती है। और ये इतने काबिल तो होते ही हैं आपकी अपर बर्थ को लोअर में बदलवा सकें। ट्रैन में लोअर बर्थ का मिलना भी मै अपर होने के फायदो में ही गिनना चाहता हूँ। एडिशनल हो जाना आपको सभा, समारोहों में मुख्य अतिथि संरक्षक, गणमान्य, विशिष्ठ अतिथि वगैरा-वगैरा बनाये जाने की हैसियत दिला देता है। यह आपकी साधारण सी लिखा-पढ़ी को विशिष्ट कर जाता है। आपका लिखा छपने और छपी किताबे बिकने की संभावनायें बढ़ाता है एडिशनल होना। ये एडिशनल होने के अपने फायदे हैं।

यार दोस्त खुश हो जाते हैं। आपसे दुःखी रिश्तेदार थोड़ा और एडिशनल कलप जाते हैं। घर में भी आपकी हैसियत बढ़ती है थोड़ी सी। बीबी को लगने लगता है कि ये आदमी इतना भी फालतू नहीं जितना मैं अब तक समझ बैठी थी। बधाई देने वालों की भीड़, दिवाली पर घर आये मिठाईयों के एडिशनल डब्बे और गुलदस्ते उसकी इस गलतफहमी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। बीबी आपको थोड़ी बहुत इज्जत से देखने लगे,विभाग की नीतियों के अलावा आप घर की नीतियों में भी सलाह देने लेने लायक मान लिये जाएं,इस लिहाज से तो अपर हो जाना फायदेमंद ही है।

बहुतेरे भोले-भाले लोग आपके एडिशनल को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जब ऐसे लोग किसी तीसरे से परिचय कराते है आपका तो बतौर कमिश्नर ही कराते है। ऐसे मौकों पर मैं ऐसे बर्ताव करता हूँ जैसे उसकी इस गलती पर मेरा ध्यान गया ही ना हो। सामने वाले की थोड़ी सी और बड़ी नमस्ते मन को खुश कर जाती है।

एडिशनल होना निश्चिंत हो जाना है। वैसे तो हिंदुस्तानी बंदा सरकारी नौकरी मिलते ही निश्चिंत हो जाता है पर एडिशनल होने की बात सबसे अलग है। स्टेट सर्विस का बंदा यह जानता है कि अब और ऊपर जाना नामुमकिन है। उसे नीचे भी धकेला नहीं जा सकता। निर्वाण हो जाने जैसा है ये। यह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाने जैसी अनुभूति है। जीते जी मोक्ष हो जाने जैसी स्थिति। आदमी को और क्या चाहिए ? सबसे ख़ास बात ये कि एडिशनल होना आपको कोट पहन कर ऑफिस जाने का मौका भी देता है। मौसम का ख़याल किए बगैर कोट पहन पाने को भी एडिशनल होने के फायदो में ही गिना जाना चाहिए। चूँकि पर्याप्त वक्त पहले एडिशनल कमिश्नर एक्साइज हो चुका था मैं। इसलिए हो चुका था क्योंकि उन दिनों इस कुर्सी के लिए बस मैं ही उपलब्ध था। आधिकारिक रूप से अब हो रहा हूँ। खुश होना बनता है मेंरा। जाहिर है मै खुश हूँ।

चिंतन

मेघा राठी

लेखक साहित्यकार हैं।

जीवन का सबसे कठिन, सबसे सुंदर और सबसे सच्चा इस्तीफ़ा

शायद इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि मनुष्य का पूरा जीवन दरअसल इस्तीफ़ों का इतिहास है। हम इस्तीफ़े को केवल नौकरी छोड़ने से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि इस्तीफ़ा एक कागज़ पर लिखा जाने वाला औपचारिक पत्र है लेकिन यदि जीवन को ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत बार इस्तीफ़ा देते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये इस्तीफे कागज़ पर नहीं होते केवल समय की मुहर होती है। ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए...मिट्टी के खिलौने, बारिश में भीगना, बिना कारण हँस देना, माँ की गोद में सो जाना, छोटी-छोटी बातों पर रूठ जाना। क्या किसी बच्चे ने कभी तय किया था कि अब उसे इन सब बातों से विदा लेनी है? नहीं, एक दिन स्कूल की किताबें भारी होने लगीं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं और बचपन बिना अनुमति लिए चला गया। हमें उससे इस्तीफ़ा देना पड़ा।

मनुष्य अपने जीवन को अपनी इच्छाशक्ति की विजय मानकर चलता है। उसे विश्वास होता है कि उसने जो पाया, अपनी मेहनत से पाया, जो खोया, वह भी उसके अपने निर्णयों का परिणाम था। वह स्वयं को अपने जीवन का निर्माता समझता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव गहराते हैं और पीछे मुड़कर देखने की दृष्टि विकसित होती है, वैसे-वैसे एक असहज सत्य सामने आने लगता है, 'जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं का निर्णय हमने कभी किया ही नहीं। हम केवल उन निर्णयों के सहभागी बने और समय आने पर उन पर अपने हस्ताक्षर करते चले गए।'

शायद इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि मनुष्य का पूरा जीवन दरअसल इस्तीफ़ों का इतिहास है। हम इस्तीफ़े को केवल नौकरी छोड़ने से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि इस्तीफ़ा एक कागज़ पर लिखा जाने वाला औपचारिक पत्र है लेकिन यदि जीवन को ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत बार इस्तीफ़ा देते हैं। अंतर केवल इतना है कि ये इस्तीफे कागज़ पर नहीं होते केवल समय की मुहर होती है।

ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए...मिट्टी के खिलौने, बारिश में भीगना, बिना कारण हँस देना, माँ की गोद में सो जाना, छोटी-छोटी बातों पर रूठ जाना। क्या किसी बच्चे ने कभी तय किया था कि अब उसे इन सब बातों से विदा लेनी है? नहीं, एक दिन स्कूल की किताबें भारी होने लगीं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गईं और बचपन बिना अनुमति लिए चला गया। हमें उससे इस्तीफ़ा देना पड़ा।

फिर यौवन आया... सपनों से भरा हुआ, ऊर्जा से लबालब। लगता था कि शरीर कभी थकेगा नहीं और समय कभी बदलेगा नहीं लेकिन समय ने वहाँ भी हमारी राय नहीं पूछी। चेहरे पर झुर्रियों की पहली रेखा खिंची, बालों का रंग बदलने लगा, आँखों पर चश्मा चढ़ गया और हमें अपनी ही जवानी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। यह संसार का शायद सबसे मौन इस्तीफ़ा है जिसके बारे में कोई घोषणा नहीं होती लेकिन जिससे कोई बच भी नहीं सकता।

हम रिश्तों में प्रवेश करते हैं और मान लेते हैं कि अब यह साथ हमेशा रहेगा। मित्र, प्रेम, विवाह, परिवार...सब हमें स्थायी लगने लगते हैं लेकिन जीवन का नियम स्थायित्व नहीं, परिवर्तन है। कोई दूर चला जाता है, कोई बिछड़ जाता है, कोई बदल जाता है और कई बार हम स्वयं बदल जाते हैं। तब भी हमें एक रिश्ते से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। यह इस्तीफ़ा सबसे अधिक पीड़ा देता है, क्योंकि इसमें दस्तख़त हाथ नहीं, हृदय करता है।

नौकरी का उदाहरण तो हर व्यक्ति के सामने है। कोई अपनी पूरी जवानी किसी संस्था को दे देता है। अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी ऊर्जा, यहाँ तक कि अपना स्वास्थ्य भी। उसे लगता है कि यही उसकी पहचान है। फिर एक दिन सेवानिवृत्ति का आदेश आता है। कोई पूछता नहीं कि अभी मन है या नहीं। बस एक हस्ताक्षर होते हैं और दशकों का साथ समाप्त हो जाता है। जिस कुर्सी को हम अपना समझ बैठे थे, वह अगले दिन किसी और की हो जाती है।

सोचिए, क्या इन घटनाओं का निर्णय हमने किया था? क्या हमने तय किया था कि किस घर में जन्म लेना है? क्या हमने अपने माता-पिता चुने थे? क्या हमने अपनी पहली साँस का समय निश्चित किया था? क्या हमने तय किया कि हमारा बचपन कब समाप्त होगा, यौवन कब ढलेगा या बुढ़ापा कब आएगा?

यदि उत्तर 'नहीं' है तो फिर यह स्वीकार करना भी पड़ेगा कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इच्छा से नहीं, समय के विधान से चलता है।यहीं से एक अत्यंत सुंदर प्रतीक जन्म लेता है 'हस्ताक्षर'।

किसी सरकारी फ़ाइल में आदेश ऊपर लिखा जाता है। नीचे केवल हस्ताक्षर करने होते हैं। हस्ताक्षर करने वाला आदेश का लेखक नहीं होता केवल उसका स्वीकारकर्ता होता है। शायद मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। समय आदेश लिखता है, प्रकृति उसे लागू करती है और मनुष्य केवल उसके नीचे अपना नाम लिख देता है।

यह विचार पहली दृष्टि में मनुष्य को असहाय बना सकता है पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन कभी भी भाग्यवाद का समर्थन नहीं करता। वह कहता है कि कर्म तुम्हारे हाथ में है लेकिन फल का विधान व्यापक है। तुम बीज बो सकते हो पर वर्षा नहीं बुला सकते। तुम नाव बना सकते हो पर हवा की दिशा तय नहीं कर सकते। तुम प्रयास कर सकते हो लेकिन समय को आदेश नहीं दे सकते।

यही कारण है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। पद मिलने पर वह स्वयं को अजेय समझने लगता है। सौंदर्य मिलने पर उसे लगता है कि यह हमेशा रहेगा। धन मिलने पर उसे विश्वास हो जाता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है लेकिन समय किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। वह राजा और रंक, दोनों से एक ही दिन इस्तीफ़ा लेता है।

संसार के महानतम सम्राट भी अपने सिंहासन बचाकर नहीं रख सके। सबसे बड़े कलाकार अपनी तालियाँ साथ नहीं ले गए। सबसे बड़े उद्योगपति अपना साम्राज्य यहीं छोड़ गए। सबसे सुंदर चेहरे समय के सामने झुक गए। तब हम किस बात का अभिमान करें?

शेक्सपीयर ने लिखा था, 'सारा संसार एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता हैं।' भारतीय दर्शन ने इससे भी पहले संसार को ईश्वर की लीला कहा। दोनों का सार एक ही है। मंच हमारा नहीं है। भूमिका हमारी पसंद की नहीं है। प्रवेश का समय हमने तय नहीं किया और प्रस्थान का समय भी हमारे हाथ में नहीं होगा।

हाँ, एक चीज़ अवश्य हमारे हाथ में है...हम अभिनय कैसा करते हैं। यही मनुष्य की असली स्वतंत्रता है। वह अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाए या छल से, प्रेम से निभाए या घृणा से, करुणा के साथ निभाए या अहंकार के साथ...यह चुनाव उसका है लेकिन भूमिका कितने समय तक चलेगी, इसका निर्णय उसके हाथ में कभी नहीं था।

आज का मनुष्य इसलिए बेचैन है क्योंकि वह हर उस चीज़ को स्थायी बनाना चाहता है जो स्वभाव से अस्थायी है। वह चाहता है कि उसका यौवन कभी समाप्त न हो, उसके प्रियजन कभी दूर न जाएँ, उसकी नौकरी कभी न छूटे, उसकी सफलता हमेशा बनी रहे लेकिन जीवन का पूरा सौंदर्य ही परिवर्तन में छिपा है। यदि ऋतुएँ न बदलें तो प्रकृति मर जाए, यदि समय ठहर जाए तो जीवन भी ठहर जाएगा।

शायद इसलिए जीवन हमें बार-बार इस्तीफ़ा देना सिखाता है। पहले खिलौनों से, फिर इच्छाओं से, फिर महत्वाकांक्षाओं से, फिर अहंकार से और अंत में स्वयं जीवन से। जो व्यक्ति इन इस्तीफ़ों का विरोध करता है, वह हर मोड़ पर टूटता है लेकिन जो उन्हें जीवन का स्वाभाविक नियम मान लेता है, वह हर विदाई में भी एक नई शुरुआत देख पाता है।

मनुष्य अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। न पद, न प्रतिष्ठा, न संपत्ति, न पहचान यदि कुछ बचता है तो केवल उसके कर्मों की सुगंध और लोगों के मन में छोड़ी गई उसकी स्मृतियाँ।

इसलिए शायद जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितनी संपत्ति अर्जित की या कितनी प्रसिद्धि पाई। असली प्रश्न यह है कि जिन भूमिकाओं के लिए हमें इस धरती पर भेजा गया, क्या हमने उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाया? क्योंकि अंत में समय हमारे सामने फिर एक फ़ाइल रखेगा। उस पर अंतिम आदेश पहले से लिखा होगा। हमें उसमें कुछ जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं होगा। हमें केवल अपने जीवन का अंतिम हस्ताक्षर करना होगा और शायद उसी क्षण समझ में आएगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति आदेश लिखना नहीं बल्कि हर अपरिहार्य सत्य को गरिमा के साथ स्वीकार करना है। वही स्वीकार जीवन का सबसे कठिन, सबसे सुंदर और सबसे सच्चा इस्तीफ़ा है।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या हो जिंदगी की सार्थकता का पैमाना ?

इस संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने के पूर्व हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का पर्याप्त आकलन तमाम संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह सच है कि यथार्थ के धरातल पर टिकी सोच के आधार पर ही भविष्य निर्माण की परिकल्पनाओं को साकार सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन जीवन में महत्वपूर्ण मुकाम पाने के लिए महत्वाकांक्षा का होना भी एक आवश्यक शर्त है। कभी-कभी वांछित लक्ष्य को पाने के लिए संभावनाओं का पूर्वानुमान भी लगाना होता है। जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर रहने के लिए हौसलों की उड़ान भी बहुत मायने रखती है। ऐसी स्थिति में हमारा आत्मबल ही हमें संबल देता है।

हर किसी की जिंदगी में मन की कोई विशेष चाहत होती है। आमतौर पर ऐसी चाहत कभी अपने लिए या कभी अपने परिवार के लिए हुआ करती है। इस संदर्भ में मन-वचन-कर्म की एकाग्रता के साथ मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है कि भरपूर प्रयासों के पश्चात भी हर कोई मनोवांछित लक्ष्य को पा सके। कई बार हम अपनी क्षमताओं का वास्तविक आकलन करने में गंभीर भूल कर बैठते हैं। इसके चलते कभी क्षमताओं का पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता तो कभी अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया जाता है। नतीजतन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते और हम निराशा के गहन अंधकार में डूब कर रह जाते है।

इस संदर्भ में आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने के पूर्व हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का पर्याप्त आकलन तमाम संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यह सच है कि यथार्थ के धरातल पर टिकी सोच के आधार पर ही भविष्य निर्माण की परिकल्पनाओं को साकार सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन जीवन में महत्वपूर्ण मुकाम पाने के लिए महत्वाकांक्षा का होना भी एक आवश्यक शर्त है। कभी-कभी वांछित लक्ष्य को पाने के लिए संभावनाओं का पूर्वानुमान भी लगाना होता है। जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर रहने के लिए हौसलों की उड़ान भी बहुत मायने रखती है। ऐसी स्थिति में हमारा आत्मबल ही हमें संबल देता है।

परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं होती। अनेक अवसरों पर ऐसे कारण एवं निमित्त बन जाते हैं कि हमें अपनी कार्ययोजना में कहीं-कहीं आंशिक परिवर्तन भी करना होते हैं। हमें ऐसे संभावित परिवर्तनों के प्रति मानसिक रूप से तैयार रहने की जरूरत होती है। कभी-कभी पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों के चलते वांछित लक्ष्य में परिवर्तन करना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में हमें भविष्य निर्माण की अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर जीवन की दशा और दिशा में तब्दीली करना भी पड़े, तो भी मन में कोफ्त नहीं होती। किसी एक ही लक्ष्य पर पूर्ण रूप से अडिग रहना आज के दौर में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता।

जब दौड़ प्रतियोगिता होती है, तब सारे धावक प्रथम आने की कामना करते हैं। लेकिन सब आ नहीं पाते। ऐसे में दूसरा, तीसरा या अंतिम स्थान भी मिले तो यह सोचकर दिल को सुकून होना चाहिए कि यही एकमात्र प्रतियोगिता जिंदगी की आखरी प्रतियोगिता नहीं थी। आगे अवसर और भी आएंगे, तब इस प्रतियोगिता में पिछड़ना भी हमारी रियाज के रूप में हमें और अधिक काबिल बनाने में सहायक होगा। लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास कभी अकारथ नहीं जाते। कहीं-न-कहीं उसका प्रतिफल देर सबेर ही सही, लेकिन मिलता अवश्य है। और कुछ नहीं तो अनुभव का लाभ तो जीवन में कभी-न-कभी काम आता ही है। इसलिए हमें प्रयास करना किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए।

जब हम विराट लक्ष्य को सामने रखकर उसे जग जाहिर कर देते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि हमें हतोत्साहित किए जाने के प्रयास होने लगे। आज के दौर में उत्साहवर्धन करने वालों की अपेक्षा मनोबल तोड़ने वालों की बहुतायत है। ऐसी स्थिति में मन की दृढ़ता ही हमारे काम आती है। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। बहुतेरे लोग वांछित लक्ष्य को पाने का प्रयास ही नहीं करते और 'मैं ऐसा कैसे कर सकूंगा ?' यह सोचकर बैठ जाते हैं। इस संदर्भ में दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां बड़ी माकूल जान पड़ती है कि 'कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।' दरअसल परिणाम चाहे जो हो, किसी भी दिशा में कुछ- न- कुछ करने का सिला मिलता ही है।

जीवन में अपने लक्ष्य के विकल्प का होना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मनचाही चाहत के सर्वथा अपूर्ण रहने पर अवसाद से घिर जाने का अंदेशा बना रहता है। संकल्प का विकल्प नित नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने की अनगिनत नई-नई राहे निकलती दिखाई देती है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते इसका संज्ञान ले लेवे। ताकि मुख्य लक्ष्य से निराश होने पर तत्काल प्रभाव से हम अपनी नई राह का चयन कर सके। वैसे भी यह जरूरी नहीं होता कि हर किसी के मन की चाहत साकार सिद्ध हो ही जाए। समय का कब कैसा दौर आएगा, इस बारे में पक्के तौर पर सटीक आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए हर एक संभावना पर विचार करना चाहिए।

सामयिक

राजेन्द्र जोशी

स्वतंत्र पत्रकार

जनजातीय छात्रावासों में अनियमितताओं का दोषी कौन?

इस घटना के विरोध में सोमवार को पीड़ित परिवार और आदिवासी सामाजिक संगठनों ने पाटी थाने का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जयस संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने बताया कि घटना की जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई हो साथ ही जिले के जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक हमसे चर्चा करें। चर्चा नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितक़ालीन धरना-प्रदर्शन के लिए विचार करेंगे। इसी को लेकर सोमवार को जनजातीय कार्य विभाग के उपायुक्त गणेश भाबर ने छात्रावास का दौरा कर कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है।

आजादी के बाद से ही मप्र के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आवासीय छात्रावासों व आश्रमों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर बनाई गई है। साल दर साल इनमे सुविधाओं और साधनों की लगातार वृद्धि होती जा रही है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ अधीक्षकों और कर्मचारियों का शोषण और लापरवाही बढ़ती जा रही है। साधनों और खाने में कमी, इलाज में लापरवाही, यौन शोषण के बाद अब तो आत्महत्या के मामले भी सामने आने लगे है। सरकारी स्तर पर मामलो की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पुनःबहाली, इससे अधिक कुछ नहीं। कुछ समय निरीक्षण, सख्ती और फिर से घटनाओं का सिलसिला जारी। ताजा घटना क्रम बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड मे स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के कन्या छात्रावास का है। यहां 25 जुलाई को कक्षा 11 वीं की 18 वर्षीय छात्रा बिन्दु का छात्रावास के कमरे में शव मिला। पुलिस मामने जांच कर रही है।

इस घटना के विरोध में सोमवार को पीड़ित परिवार और आदिवासी सामाजिक संगठनों ने पाटी थाने का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जयस संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने बताया कि घटना की जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई हो साथ ही जिले के जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक हमसे चर्चा करें। चर्चा नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितक़ालीन धरना-प्रदर्शन के लिए विचार करेंगे। इसी को लेकर सोमवार को जनजातीय कार्य विभाग के उपायुक्त गणेश भाबर ने छात्रावास का दौरा कर कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है।

इसके पूर्व निवाली मे स्थित जनजातीय विभाग के एकलव्य आदिवासी कन्या छात्रावास में कक्षा 9वीं की छात्रा ने 13 जनवरी की रात्रि में भोजन के बाद आत्महत्या कर ली थी। फरवरी 2025 के शुरुआती सप्ताह में बड़वानी जिले के ग्राम पलसूद के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की बालिकाओं द्वारा छात्रावास अधीक्षिका और बीईओ पर बेड टच और यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पुलिस थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया था। शिकायत के चलते जयस द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन के बाद अधीक्षिका के खिलाफ पाक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया था।

इस मामले में छात्राओं का कहना है कि अधीक्षिका द्वारा उन्हें बुलाया गया जहां बीईओ को होस्टल दिखाने के दौरान कक्ष में बीईओ ने बेड टच किया और इंदौर साथ चलने का प्रस्ताव दिया। वहीं, दूसरी छात्रा ने बताया कि 29 जनवरी को विदाई कार्यक्रम के दौरान अधीक्षिका से साड़ी पहनने में मदद मांगी तो उन्होंने बेड टच करके वीडियो बनाया। मामला दर्ज होने के बाद फरार अधीक्षिका की 10 दिनों बाद गिरफ्तारी हो पाई थी।

जुलाई 2023 में एकलव्य आवासीस विद्यालय परिसर बूंदी जिला बडवानी में एक छात्रा ने चाकू से हाथ की नस काट ली थी। इसे सामान्य घटना बताकार टाल दिया गया था। एक अन्य घटना में इसी एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने फरवरी 2024 में अधीक्षक, अतिथि शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर डराने धमकाने व वीडियो बनाने की शिकायत करने हेतु छात्रावास से जिला मुख्यालय कि ओर पैदल मार्च कर दिया था। घटना की जांच उपरान्त 4 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी तथा एक को निलम्बित और एक को अन्यंत्र अटैच किया गया था।

ताजा घटनाओं ने जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित होने आश्रमों, छात्रावासों की अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। अभी तक छात्रावासों में फूड पायजनिंग, बीमारी की स्थिति में समय पर इलाज नहीं मिलना, मीनू अनुसार भोजन-नाश्ता नहीं मिलना, सफाई का अभाव सहित अन्य अनियमितताएं देखने सुनने में आती रही है, लेकिन आत्महत्याएं बता रही हैं कि भ्रष्टाचार और आर्थिक सम्पन्नता के चलते छात्रावास अधीक्षकों पर किसी का अंकुश नहीं है। हर साल, हर महीने प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्रावासों में अनियमितताओ के मामले सामने आते रहते है।

जनजातीय कार्य विभाग के बालक-बालिका छात्रावासों में अधीक्षक बरसों से जमे हैं जबकि नियम 3 वर्ष का है। अधिकांश जगह अधीक्षक रात्रि के समय छात्रावासों में नही रहते है। अनियमितता पाये जाने पर हटाये गये अधीक्षक कुछ समय बाद पुनः छात्रावास में पदस्थ हो जाते हैं। छात्रावासों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण मात्र औपचारिक रहता है। डर के मारे छात्र-छात्राएं अधीक्षक के विरूद्ध बोल नही पाते हैं। निरीक्षण के समय ही छात्रावासों की व्यवस्था सुधरती है, उसके बाद वही हाल।

कुछ मामलों के सामने आने से अव्यवस्थाओं पर चर्चा होती है, अगर गहराई से पड़ताल हो तो चौंकाने वाले आंकड़ें सामने आना तय है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित बालक-बालिका छात्रावासों में अनियमितताओं की शिकायत आम है, जब कोई बडी घटना घटती है तब छात्रावासों के निरीक्षण और संचालन की गाइड लाइन बनाई जाती है,लेकिन उसके बाद फिर से ढांक के तीन पात।

विवेक मिश्रा

प्रशासनिक के साथ नैतिक सुधार भी जरूरी

छात्र सरोकार से सम्बद्ध नीट पेपर लीक का मामला, अंततः शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के साथ शांत हुआ। प्रतीत होता है। यह कितना स्थाई होगा, उत्तरोत्तर इस पूरे आंदोलन की स्पष्ट नीयत और प्रामाणिकता को स्पष्ट करता चलेगा। भारत सरकार ने युवा आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी प्रचलित कार्यशैली में परिवर्तन किया है। कॉकरोच समूह को भी अब संयम व मर्यादाओं में रहकर व्यवस्थाओं में सुधार की प्रक्रियाओं का आसरा रखना चाहिए। वहीं छात्रों को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि उनके हितों के मुद्दों पर कितना समाधान हुआ, कितनी राजनीति हुई और किन तरीकों और भाषाओं से भारत की कैसी तस्वीर, क्या छवि विश्व में पहुँची है।

इन सब के बीच यदि इस पूरे आंदोलन को समेट के हम देखना चाहे तो उत्पत्ति से लेकर ध्येय प्राप्ति तक, संपूर्ण घटनाक्रम संवाद,सुधार और संस्कार की कमी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। आंदोलन की शुरुआत से ही ऐसे कई अवसर आए, जिनपर संवाद स्थापित कर उन दृश्यों से बचा जा सकता था, जिनसे देश की छवि धूमिल हुई, चाहे फिर संसद की तरफ उपद्रव करते हुए बढ़ती भीड़ रही या उन्हें रोकने के लिए मजबूरन की गई सख्त कार्रवाई की चपेट में आए छात्रों के ज़ख्म हो। सोशल मीडिया के अत्यंत मुखर दौर में सरकार से, खासकर प्रधानमंत्री जी से जनसामान्य की यह आकांक्षा रही है कि, वह जनसरोकार के हर एक मुद्दे पर अपना पक्ष रखें, यह उम्मीदें यूपीए सरकार में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री से भी की जाती थी, जिसे लेकर उनकी तीखी आलोचना हुईं। प्रायः संवैधानिक पद पर रहते हुए फौरी तौर पर हर विषय पर टिप्पणियां करना संभव नहीं होता है, पर बात इन दिनों लंबी खामोशी की भी रही। आज सोशल मीडिया में अधिकतर समय गुजारने वाले युवा तो इस बात पर विशेष ध्यान रखते हैं कि, किसी विषय पर नेतृत्व के द्वारा कोई टिप्पणी की गई है या नहीं। दरअसल सर्वेसर्वा द्वारा स्थापित संवाद, सांत्वना व आश्वासन का सूचक होता है।

महीने भर चले धरने के मध्य सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद हुआ होता तो, शायद इस कथानक का पटाक्षेप कहीं अधिक सौहार्द्रपूर्ण माहौल में होता।

आंदोलन का सबसे सार्थक उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाना और परीक्षा आयोजकों की जवाबदेही तय करना था। आंदोलनकारियों के पास सरकार के लिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु कोई निश्चित सुझावात्मक मसौदा आंदोलन की शुरुआत से तैयार नहीं था। ध्यान सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर केंद्रित था। ऐसे में सरकार के पास भी संवाद स्थापित करने या धरने, भूख हड़ताल को खत्म करने की पहल करने संबधी कोई ठोस आधार न था। भारत सरकार संवाद करती भी तो किस विषय पर, 18 जुलाई तक तो जंतर-मंतर से केवल इस्तीफ़े की बात चल रही थीं। 20 जुलाई को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल और आंदोलनकारियों का दल आमने सामने बैठा था तब मंत्रीगण ने शिक्षा में सुधार का सुझावात्मक मसौदा आंदोलनकारियों से मांगा तो, आंदोलनकारियों द्वारा असमर्थता व्यक्त कर, आगामी दिवसों में इसे सामने रखने का समय मांगा गया। यह वाकया, आंदोलन की गंभीरता को स्पष्ट करता है, आंदोलन सुधार के प्रति लक्षित था या सिर्फ इस्तीफे पर प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ? दूसरी ओर सरकार भी नीट पेपर लीक के बाद, द्वितीय अवसर की सफल परीक्षा पूर्ण कर आश्वस्त हो गई थी कि यह मामला शांत हो गया है। जबकि एनटीए में पारदर्शिता, जवाबदेही अभी भी बाकी थी। यही शिथिलता जन आक्रोश में परिवर्तित हुई। हालाँकि सुधारवादी दृष्टिकोण धीर, गम्भीर व सहयोगात्मक रहना चाहिए, न कि अड़ियल। इस्तीफे जवाबदेही और सुधार के संकेतक हो सकते हैं, पर मानक नहीं। यह तो उत्तरदायित्व से भागने का सरलतम उपाय रहे हैं। जिस से गलती हुई,उस से सुधार करवाना और जहां गलत हुआ वहां सही कराना, अधिक चुनौतीपूर्ण और जवाबदेह दृष्टिकोण होता है। इस्तीफे देने की प्रवृति का पुनर्जागरण कराना तो, सरकारों को और अधिक भायेगा।

शिक्षा में सुधार से तात्पर्य केवल नीतिगत सुधार से नहीं होना चाहिए, आज की आवश्यकता है कि, शिक्षा में नैतिक सुधार भी प्रतिपादित किए जाएं। इस क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष इस आंदोलन की प्रकृति से जुड़ा रहा है। जेन जी, याने चौदह से उन्नतीस आयुवर्ग के लोगो की अगुवाई में खड़ा हुआ यह आंदोलन, अपनी विलक्षण रचनात्मक व व्यंग्यात्मक शैली को लेकर सर्वत्र चर्चित हुआ है। किंतु इसी के साथ अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणियों और अमर्यादित हरकतों से बदनाम भी हुआ है। मीडिया के एक समूह के प्रति जैसी उग्र असहिष्णुता दिखाई गई , महिलाकर्मियों के साथ की गई बदसलूकी हो या कम उम्र के बच्चे जिस प्रकार देश के बुजुर्ग प्रधानमंत्री को भद्दी गालियाँ देते, देखे व सुने गए हैं। यह दृश्य नई पीढ़ियों में खत्म होते नैतिक मूल्यों की ओर गम्भीर इशारा करते हैं। इस तथ्य से शायद ही कोई मुँह फेरे कि गालियाँ हर पीढ़ी की दुर्वृत्ति रही है,लेकिन इस तरह सार्वजनिक मंच से गौरवपूर्ण मंडन शायद ही कभी किया गया। आंदोलन की नवीनता से मुग्ध हो यदि हम इस तथ्य को न्यू नॉर्म (नया मानदंड) बना दें तो यह भारतीय सभ्यता के प्रति हम भारतीयों का सबसे बड़ा अन्याय होगा। जिम्मेदारी तो दोनों पक्षों की तय होना चाहिए, पुलिस कार्यवाही हो या प्रदर्शनकारियों के उपद्रव और अभद्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के पास कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी, जिसमें वह तय कर सकें कि कौन अहिंसक आंदोलनकारी हैं और कौन शांतिप्रिय? देशभर के संगठनों, छात्रों और विपक्षी दलों से आंदोलन के समर्थन में दिल्ली पहुंचने का आव्हान कर दिया गया, जिनपर सीजेपी के नेतृत्व का कोई नियंत्रण नहीं था। जब बवाल हुआ तो इन्हें बाहरी तत्व बता कर जवाबदेही से पल्ला झाड़ दिया गया।

भारतीय जेन जी के संबंध में विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थानों ने शोधसार दिया है,जिसमें डेलॉयट और मैकेंज़ी जैसे संस्थान प्रमुखता से कुछ बातों को रखते हैं। आज का 73% भारतीय जेनजी, आर्थिक रूप से स्वयं को पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस करता है। बावजूद इसके, जेन जी सोशल मीडिया की परफेक्ट दुनिया की चाहत रखता है, जिसमें कमी आने पर वह खुद को कमतर आंकता है। भारतीय जेन जी के संबंध में एक रिपोर्ट कहती है कि, इन्हें कार्यस्थल पर जब अपने अनुरूप वातावरण नहीं मिलता है तो यह तुरंत जॉब हॉपिंग (जल्दी जल्दी नौकरी बदलने) में लग जाते हैं। ज्वाइनिंग के मात्र 60 से 90 दिनों में ही कंपनी कल्चर अनुकूल नहीं पाते हैं तो रिवेंज क्वीटिंग या त्वरित इस्तीफे का विकल्प अपना लेते हैं। यह सभी सर्वे इस जनरेशन की अस्थिर मनोदशा को चिन्हित करते हैं, ऐसे में यदि व्यवस्थागत परिवर्तन केवल इनके सदृश होने लगेंगे, तो देश की स्थिर शासन सत्ता के लिए दीर्घकालिक विचलन पैदा होगा। इसका प्रमाणिक साक्ष्य हमने नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में देखा है, जहां ऐसे आन्दोलनों के बाद कोई स्थिर मजबूत सरकार सत्ता में नहीं है। भारत को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, कि सत्ता और जनता दोनों संयुक्त प्रयासों से - संवाद को साध लें, सुधार को अवसर दें और संघर्ष में संस्कार रखें।

अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर ने समीपवर्ती ग्राम डुंडादेह आंगनवाड़ी का किया निरीक्षण

सोहागपुर। अनुविभागीय अधिकारी डॉ. बबीता राठौर ने समीपवर्ती ग्राम डुंडादेह आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। इस अवसर अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी में उपस्थित बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी गतिविधियों एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। वहीं आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका से केन्द्र में पंजीकृत एवं उपस्थित बच्चों की संख्या की जानकारी लेकर अनुपस्थित बच्चों को नियमित रूप से केन्द्र नहीं आने के कारणों की समीक्षा की। आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश दिए कि

प्रत्येक पात्र बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करके आवश्यकतानुसार उनके अभिभावकों से सतत संपर्क रखा जाए। अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर ने निरीक्षण के दौरान केन्द्र में साफ-सफाई, बच्चों को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता एवं समय पर वितरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं तथा पोषण संबंधी गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उल्लेखनीय है कि ग्राम डुंडादेह की महिलाओं ने हाल ही में ग्राम में नशे की समस्या के संबंध में जिला जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके उपरांत एसडीएम डॉ. बबीता राठौर द्वारा ग्राम में रात्रि चौपाल आयोजित कर महिलाओं से संवाद किया गया था। प्रशासन द्वारा ग्राम में नशामुक्त एवं स्वस्थ सामाजिक वातावरण के निर्माण के साथ-साथ महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हर्षोल्लास से मनेगा राष्ट्रीय पर्व, नवीन बस स्टैंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होगा

सोहागपुर। नवीन बस स्टैंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों एवं विभिन्न शालाओं में विभाग प्रमुख झंडा फहराएंगे। इसी संबंध को लेकर जनपद पंचायत परिसर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की रूपरेखा बनाने संबंधी बैठक अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल,

उपाध्यक्ष राघवेंद्र पटेल, तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर,नपाध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्विनी सरोज नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ श्रीराम सोनी, बीईओ आदि की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस बैठक में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी।

नशामुक्ति अभियान सफल बनाएं- इसी अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल ने प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति का अभियान को सफल बनाने में समस्त नागरिकों से आव्हान किया। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों सोमनाथ आदिवासी संगठन के संयोजक राजकुमार रघुवंशी के साथ आदिवासी महिलाओं ने अवैध शराब बनाने व बिक्री पर रोक के लिए नर्मदापुरम जाकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा से ग्राम की शराब से हो रही सामाजिक दुर्दशा से अवगत कराया था। वहीं इसी संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर ने भी आदिवासी ग्राम डुंडादेह पहुंच कर ग्राम को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया था। बैठक में शराब बंदी अभियान चलाने वाली मातृशक्ति को सम्मानित करने की बात कही गई। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख विधालय प्रतिनिधि, पत्रकार गण आदि उपस्थित थे।

पेट्रोल पंप में तोड़फ़ोड़ और कर्मचारी से मारपीट करने वाले चौथा फरार आरोपी गिरफ्तार, पूरे नेटवर्क का किया खुलासा

पूर्व में हो चुकी है मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी

बैतूल। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट एवं तोड़फ़ोड़ प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्व में मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिव शक्ति पेट्रोल पंप खेड़ी में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट, तोड़फ़ोड़ एवं एससी/एसटी एक्ट से संबंधित गंभीर प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। 19 जुलाई की रात्रि लगभग 9.00 बजे ग्राम अखतवाड़ा खेड़ी स्थित शिव शक्ति सेल्स पेट्रोल पंप पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी राजेश शेषकर के साथ पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी अनुराग उर्फ अरुण मालवीय एवं उसके 9-10 साथियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। आरोपियों द्वारा फरियादी को जातिसूचक शब्दों से

अपमानित किया गया तथा पेट्रोल पंप कार्यालय में तोड़फ़ोड़ कर कांच क्षतिग्रस्त किए गए एवं जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 296(बी), 115(2), 351(2), 191(2), 331(6), 324(2) बीएनएस एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(1ए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में मुख्य आरोपी अनुराग उर्फ अरुण मालवीय को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। इसी क्रम में पुलिस टीम ने दबिश देकर केतन पाल पिता अशोक पाल निवासी गणेश मंदिर के पास खंजनपुर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी के द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। प्रकरण में पुलिस द्वारा उक्त वारदात का मास्टरमाइंड भीम उर्फ अनूप सोनकर को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बनाया है, जिसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र की जावेगी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उप निरीक्षक राकेश सरयाम, उप निरीक्षक बसंत कुमार अहके, सहायक उप निरीक्षक प्रवीण पचौरी, प्रधान आरक्षक नानकराम तथा आरक्षक ओंकार, उज्ज्वल, महेश नगदे सहित थाना कोतवाली पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

गुरुपूर्णिमा पर माँ सरस्वती एवं महर्षि सांदीपनि गुरू का पर्व मनाया

बैतूल। बी.आर. अंबेडकर बी.एड. कालेज में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर महर्षि सांदीपनि गुरू पर्व का आयोजन किया गया। कार्यकम की शुरूआत महाविद्यालय के संचालक इंजीनियर ध्रुवप्रकाश अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉ. जी.डी. देशमुख द्वारा माँ सरस्वती एवं महर्षि सांदीपनि की पूजा

अर्चना की गई। बी.एड. स्कालर्स द्वारा माँ सरस्वती वंदना की गई। डॉ. देशमुख ने कहा कि यह पर्व गुरू शिष्य परम्परा का जीवंत उदारहण है। गुरू अपने शिष्य को सद्मार्ग के लिये प्रेरित करता है। वरिष्ठ व्याख्याता सुनील वर्मा ने कहा कि महर्षि सांदीपनि भगवान श्रीकृष्ण के गुरु थे, जो उज्जैन में आश्रम में शिक्षा देते थे। सांदीपनि अंलकरण समारोह 2026 का लाईव प्रसारण महाविद्यालय के सभागार में बी.एड. स्कालर्स एवं स्टाफ की उपस्थिति में देखा गया।

शिशु वाटिका में गुरू पूर्णिमा एकलव्य नाटिका की प्रस्तुति, पंडित श्री मुद्गल जी ने कहा हमारे संस्कार ही हमें पहचान देते हैं

सोहागपुर। सरस्वती शिशु मंदिर परिसर की शिशु वाटिका में गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिशु वाटिका के नन्हे छात्र छात्राओं ने उत्सुकता से कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विद्यालय में गृहस्थ पंडित प्रकाश मुद्गल ने कहा कि हमारे संस्कार ही हमारी पहचान बनती है । हम सभी को गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए एवं जीवन में गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं । आज महर्षि वेदव्यास जी की जयंती है महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण चार वेद उपनिषद की रचना की थी। भगवान रामचंद्र जी तथा भगवान कृष्ण ने भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी ।श्री मुद्गल जी ने अपने उद्बोधन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपने माता-पिता एवं गुरु की बात मानते हुए मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आज का दिन भारतीय सनातन संस्कृति के लिए बड़ा ही महत्व का दिन है । इसी अवसर पर समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल ने कहा कि गुरु हम सब के मार्ग को प्रशस्त करता है । हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए तथा गुरुओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर गुरु द्रोणाचार्य एवं उनके शिष्यों के द्वारा रचित नाटक का प्रदर्शन भी किया गया । नाटक का यथार्थ यह था कि किस प्रकार एकलव्य ने अपने अंगूठा गुरु के कहने पर गुरु को दान कर दिया था और गुरु की आज्ञा का पालन किया था।इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर संचालन समिति पदाधिकारी प्राचार्य अशोक कुमार दुबे , आचार्य, दीदी , भैया बहिनें आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने ग्राम रामघाटी पहुंचकर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य दुकान का किया निरीक्षण

प्राथमिक शाला में मूलभूत सुविधाओं की कमी पर बीआरसी और डीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को भैंसदेही विकासखंड के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर विकास कार्यों एवं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम रामघाटी पहुंचकर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य दुकान एवं पंचायत की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्राथमिक शाला हनुमानढाना रामघाटी के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पानी, शौचालय, बिजली एवं फर्नीचर संबंधी शिकायतें सामने आने पर कलेक्टर ने बीआरसी एवं डीपीसी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत के माध्यम से विद्यालय तक पहुंच मार्ग का समतलीकरण कराए जाने के भी निर्देश दिए। इसके पश्चात आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र रामघाटी के निरीक्षण के दौरान केंद्र में बिजली व्यवस्था नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से ओपीडी की जानकारी प्राप्त की। वहीं

ओपीडी रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित एएनसी जांच, खून की जांच, सिकल सेल जांच सहित ह्यूमैनाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।

अधूरे निर्माण पर जाहिर की नाराजगी- शासकीय उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गेहूं एवं चावल के स्टॉक तथा हितग्राहियों को किए जा रहे वितरण की व्यवस्था की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं होने तथा बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य अपूर्ण पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने पंचायत सरपंच को स्कूल एवं आंगनवाड़ी में बिजली, पंखे एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर में अपूर्ण बाउंड्री वॉल के भुगतान की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधान पाठक से विद्यालय में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी ली, लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने पर उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से पंचायत के नियमित रूप से खुलने, पटवारी एवं सचिव के प्रतिदिन उपस्थित होने सहित पंचायत की कार्यप्रणाली के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में आ रही समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारी को ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत किए जाने पर कलेक्टर ने जीआरएस एवं सचिव को स्वीकृत हितग्राहियों की सूची पंचायत भवन में चस्पा किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सचिव से पंचायत में संचालित निर्माण कार्यों की भी जानकारी ली।

ग्रामीणों ने नल-जल योजना से संबंधित समस्याएं भी कलेक्टर के समक्ष रखीं। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने तथा संबंधित इंजीनियर को नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को 10 सितंबर तक पानी की टंकी का निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए।

सोहागपुर पुलिस ने अंधे कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार किया

सोहागपुर। सोहागपुर पुलिस ने विगत मार्च को समीपवर्ती ग्राम निभौरा नहर किनारे मिले शव के अंधे कत्ल के मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा एस. थोटा आईपीएस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक राजन के निर्देशन में तथा श्रीमान एसडीओपी संजू चौहान के मार्गदर्शन में एवं नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोहागपुर थाने के अपराध क्र. 466,26 धारा 103(1), 296(बी), 351(3) बीएनएस के गंभीर हत्या के मामले में आरोपी राजा साहू को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी ने अंधे कत्ल का संक्षिप्त विवरण देते बताया कि दिनांक 04 मार्च 26 को बड़ी नहर के पास समीपवर्ती ग्राम निभौरा में नहर किनारे एक अज्ञात पुरूष का शव पड़े होने की सूचना सोहागपुर पुलिस थाने में दी गई थी।इस मामले में पुलिस ने मर्ग क्रमांक. 27/26 धारा 194 बीएनएसएस का कायम करके जांच में लिया गया था। इस मर्ग जांच के दौरान

अज्ञात मृतक पुरूष की पहचान विनोद उर्फ भूरा पिता ब्रजलाल मेहरा उम्र 19 साल नवीन पुलिस थाने के पीछे सुभाष वार्ड सोहागपुर के रूप में हुई थी। इस मर्ग की जांच में परिजनों एवं चश्मदीद साक्षी के कथन , पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया ।कि रंगपचमी के दिन भूरा उर्फ विनोद उसका दोस्त राजा साहू, सन्नी साहू के साथ पार्टी करने के लिए बड़ी नहर ग्राम निभौरा गए थे । यहां शराब पीते समय राजा साहू एवं भूरा उर्फ विनोद मेहरा के बीच अचानक विवाद गाली गलौच होने लगा था इसी बात को लेकर नहर पार करते समय राजा साहू ने भूरा मेहरा को धक्का देकर नहर में गिरा दिया था।जिससे नहर के पानी में डूबने के कारण भूरा मेहरा की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच उपरांत अभियुक्त राजा साहू पिता राकेश साहू उम्र 25 साल निवासी सुभाष वार्ड सोहागपुर के विरूद्ध अपराध क्र. 446/26 धारा 103(1), 296(बी), 351(3) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी राजा साहू को गिरफ्तार कर लिया गया।घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जप्त की गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया कर दिया है।।

महत्वपूर्ण भूमिका: नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी, उप निरीक्षक विवेक यादव, सहायक उपनिरीक्षक मुकेश नामदेव, सहायक उपनिरीक्षक गणेश राय, आरक्षक 744 मनोहर दायमा, आर.क्षक 558 राजेन्द्र सिंह तोमर, आरक्षक. 616 अजमेर सिंह परिहार, आरक्षक 477 विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

संक्षिप्त समाचार

जिला चिकित्सालय एनआरसी की देखरेख में कु.रश्मि ने जीती कुपोषण से जंग

बैतूल (निप्र)। बैतूल के अंबेडकर वार्ड निवासी कु.रश्मि धाड़से ने कुपोषण से जंग जीती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि कु. रश्मि पिता राजू धाड़से उम्र 5 वर्ष का वजन उम्र अनुसार नहीं बढ रहा था। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान रश्मि को कुपोषण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता कनोजे द्वारा 11 मई 2026 को एनआरसी जिला चिकित्सालय बैतूल में भर्ती कराया गया। भर्ती के समय रश्मि का वजन 10.360 किग्रा था। जिला चिकित्सालय एनआरसी प्रभारी चिकित्सक डॉ सुरेन्द्र कुशवाहा की निगरानी में बच्चों को वजन अनुसार पोषण आहार थेरेपेटिक डाइट एवं आवश्यकतानुसार औषधि उपचार प्रदान किया गया। श्रीमती ऊषा पोटफोडे पोषक प्रशिक्षक द्वारा माता को कंगारू मदर केयर, सही तकनीक से घर पर देखभाल, पौष्टिक आहार, स्वच्छता के लिए परामर्श दिया गया। रश्मि की निरंतर देखभाल एवं उपचार के परिणाम स्वरूप 11 दिवस में ही वजन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके बाद 21 मई 2026 को डिस्चार्ज के समय रश्मि के वजन 11.225 किग्रा दर्ज किया गया। रश्मि अब पूर्णत: स्वस्थ है। परिजन ने शासन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एनआरसी स्टाफ को धन्यवाद दिया है।

मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 7 प्रकरण दर्ज

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल ने रविवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध हाईवे किनारे शराब पिलाने वाले रेस्टोरेन्ट पर कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने प्रिंस ढाबा, पंडित जी ढाबा मनियाखेड़ी व उसकल्ली, सांवरिया ढाबा, राजपूत ढाबा उसकल्ली, चंपा दादा ढाबा नांदवा, राजस्थान ढाबा के साथ-साथ बिरजाखेड़ी, टिमरनी व चारखेड़ा में छापेमारी की। इस दौरान 44 पाव देशी मदिरा प्लेन, 8 पाव ऑफिसर च्वाइस, एक-एक बॉटल सिग्नेचर व्हिस्की एवं वी21 वोडका एवं 210 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 7 प्रकरण दर्ज किये। जप्त किये गये मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 28559 रूपये है।

ग्राम कायदा में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विवेक शर्मा के मार्गदर्शन तथा वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती सुचिता इक्का के नेतृत्व में शासकीय पी एम श्री हायर सेकंडरी स्कूल कायदा में वन स्टॉप सेंटर एवं मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर केस वर्कर सुश्री रितु राजपूत ने छात्र-छात्राओं को वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्र में दी जाने वाली परामर्श सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, आश्रय सहायता, चिकित्सा व पुलिस सहायता, विभिन्न हेल्पलाइन नंबर महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सहायता 112, साइबर अपराध से सुरक्षा नंबर 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण कानून, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को संरक्षण, गोद लेना, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, संघर्षरत बच्चों का मानसिक-सामाजिक सहयोग आदि की जानकारी देते हुये बाल विवाह के दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में शासकीय पी एम श्री हायर सेकंडरी स्कूल कायदा के प्रभारी प्राचार्य श्री कमल सिंह भलावी, शिक्षकगण एवं छात्र- छात्राओं और वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ कार्यक्रम में उपस्थित रहा।

स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करें: कलेक्टर अंशुल गुप्ता

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कहीं भी जलापूर्ति में व्यवधान नहीं आना चाहिए और इसके लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं समय रहते की जाएं। कलेक्टर श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित पेयजल व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाए तथा जिन स्थानों पर हैंडपंप, नल-जल योजना या अन्य जल स्त्रोतों में किसी प्रकार की समस्या हो, उसका तत्काल निराकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वर्षाकाल के दौरान जल स्त्रोतों की विशेष निगरानी रखें तथा किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों और नौनिहालों को पेयजल संबंधी किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बैठक में विभागीय अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूली बच्चों के दस्तावेज बनाए जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि आधार, समग्र से लेकर प्रत्येक दस्तावेज के बनाए जाने में कोताही ना बरती जाए जो भी आवश्यक कार्यवाहीयां है वह पूर्ण कर लें। अधिकारियों से कहा कि दस्तावेज तैयार कराने से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं एवं कार्यवाहियां समय रहते पूर्ण कर ली जाएं, ताकि बच्चों एवं उनके अभिभावकों को अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के कार्यों के संबंध में विशेष निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

■ स्कूल फीस और पाठ्यपुस्तकों की विक्रय दरों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो, गड़बड़ी पर निगरानी कर कार्यवाही की जाएं

जनसमस्याओं से जुड़े आवेदनों का गंभीरता से निराकरण किया जाए : कलेक्टर डॉ. सोनवणे

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आबकारी विभाग को विशेष रूप से चोपना और सालबर्डी क्षेत्र में लगातार सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध खनन के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभाग निर्धारित समय में जनहित और जनसमस्याओं से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। बैठक में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने निजी स्कूलों में अनावश्यक फीस वृद्धि और पाठ्य पुस्तकों सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री के विक्रय पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

सभी विद्यालयों में शौचालय, पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसहयोग से विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बेंच उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने एमपीआरडीसी को प्रभातपट्टन के चारसी और सालबर्डी में खराब सड़कों की मरम्मत एवं रोड मार्किंग कराने के निर्देश दिए। सभी स्थानांतरित पटवारियों को तत्काल नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश देते हुए सख्त हिदायत दी कि ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाशिंदा, ग्वासेन और ढोंडरामहू सहित अन्य ग्रामों में विद्युत आपूर्ति सुधारने के निर्देश भी दिए।

लोक सेवा गारंटी प्रकरणों की समीक्षा के दौरान समय-सीमा से बाहर आवेदन लंबित पाए जाने पर चोपना के नायब तहसीलदार पर अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एसडीएम, जनपद सीईओ और तहसीलदारों को छात्रावासों, आंगनवाड़ियों और स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने तथा मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता स्वयं परखने के निर्देश दिए। भीमपुर के ग्राम करिंदा में जलभराव की समस्या के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने दुर्गम और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए वायरलेस सिस्टम और एम्बुलेंस व्यवस्था सुदृढ़ करने को कहा। बैठक में बिना अनुमति अधिकारी-कर्मचारियों के अटैचमेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यों में खानापूर्ति या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे अधिकारियों के कार्य व्यवहार का उल्लेख सेवा पुस्तिका में किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत जामठी में जनजातीय भूमि पर दुकान निर्माण के मामले में सरपंच को नोटिस जारी करने तथा संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित जनपद सीईओ को तीन दिन में सुधार सुनिश्चित करने और प्रगति नहीं होने पर वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जनसुनवाई, संबल पंजीयन, अनुग्रह सहायता एवं अंत्येष्टि सहायता के लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों, ग्रामों में क्लोरीनेशन तथा मानसून के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों को पेयजल गुणवत्ता बनाए रखने और जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में कलेक्टर ने आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने तथा पूर्वाभ्यास कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर कामिनी ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार हेतु फसल बीमा जागरूकता रथ रवाना

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में खरीफ मौसम 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने एवं अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से फसल बीमा जागरूकता रथ को रवाना किया गया। यह रथ जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों को योजना की जानकारी देगा तथा फसल बीमा के लाभों के बारे में जागरूक करेगा। जागरूकता अभियान के दौरान किसानों को वर्तमान मौसम परिस्थितियों एवं संभावित अल नीनो के प्रभावों से अवगत कराते हुए समय सीमा के भीतर अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत

सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में उपलब्ध बीमा सुरक्षा एवं दावा प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों के लिए कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि सोयाबीन हेतु 758 रू प्रति हेक्टेयर, धान (सिंचित) हेतु 1,020 रू प्रति हेक्टेयर, धान (असिंचित) हेतु 684 रू प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 604 रू प्रति हेक्टेयर, तुअर/अरहर हेतु 714 रू तथा उड़द हेतु 486 रू (जिला स्तर) निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने के इच्छुक किसान अपने निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, अधिकृत चौनल, जन सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृषकों के लिए फसल बीमा कराने हेतु बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज (बही) तथा बटाईदार/पट्टेदार किसानों के लिए भूमि स्वामी का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उप संचालक कृषि श्री के.पी. भगत ने फसल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बदलते मौसम और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक किसान समय रहते अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके तथा इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का लाभ उठाएं।

में कलेक्टर विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन तथा योजनाओं की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सीएम हेल्पलाईन, विभागीय गतिविधियों, समय सीमा वाले पत्रों, योजनाओं तथा अभियानों की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

उन्होंने विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाईन का समयावधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। कोई भी शिकायत जबाव दर्ज किए बिना लेवल जम्प नहीं हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने 50 दिवस से अधिक समयावधि की सीएम हेल्पलाईन की विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को सात दिवस में निराकरण हेतु निर्देशित किया। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभिन्न विभागों के समय सीमा वाले पत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में पीएम आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पट्टा वितरण की कार्यवाही की जानकारी लेते हुए सभी सीएमओ को पात्रतानुसार स्वीकृति की कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्रता से निराकृत कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया। बैठक में कृषि विभाग, सहाकारिता, सामाजिक न्याय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के कार्यो तथा योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर्स तथा जिला अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

हर स्कूल विद्यार्थी के परिवहन की रहे पूरी जानकारी

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने निर्देश दिये है कि स्कूलों में बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों की पूरी जानकारी संकलित की जाए। साथ ही कौन-से वाहन में कौन सा बच्चा स्कूल आना जाना कर रहा है, जिला शिक्षा विभाग यह जानकारी भी अद्यतन करे। सोमवार को आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि निराश्रित गोवंश का सड़कों पर जमावड़ा न हो, ऐसे गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। बैठक में उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में जल कर वसूली पर भी जोर दिया।

नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवारा सुअरों के नियंत्रण करने के लिये बैठक में निर्देश दिये गये। बैठक में बताया गया कि एक अगस्त को हरदा की कृषि उपज मण्डी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजन का समय अपरान्ह 1 बजे से 4 बजे के बीच रहेगा। इस महोत्सव में सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम कुमार, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रवीण इवने सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

मानसून की फुहारों के बीच दौड़ा उत्साह, पचमढ़ी मानसून मैराथन-2026 का भव्य आयोजन

1600 से अधिक धावकों ने दिखाई फिटनेस की मिसाल

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढ़ी की मनमोहक वादियों में आयोजित 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन-2026 खेल, पर्यटन और प्रकृति प्रेम का अद्भुत संगम बनकर उभरी। मानसून की हल्की फुहारों, धुंध से आच्छादित सतपुड़ा की पर्वतमालाओं और हरियाली से भरपूर प्राकृतिक वातावरण के बीच आयोजित इस मैराथन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 1600 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन का शुभारंभ नर्मदापुरम सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी एवं मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं एडवेंचर्स एंड यू के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस आयोजन में धावकों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी शामिल हुए।

चार श्रेणियों में आयोजित हुई मैराथन : हर आयु वर्ग एवं क्षमता के प्रतिभागियों को ध्यान में रखते हुए मैराथन का आयोजन चार श्रेणियों में किया गया। इसमें सुबह 6 बजे 42 किलोमीटर फुल मैराथन, सुबह 6:45 बजे 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, सुबह 7:45 बजे 10 किलोमीटर दौड़ तथा सुबह 8 बजे 5 किलोमीटर फन रन का शुभारंभ किया गया।

ऊंचाई एवं उतार-चढ़ाव वाले चुनौतीपूर्ण पर्वतीय मार्गों पर आयोजित 42 किलोमीटर फुल मैराथन इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रही, जिसने प्रतिभागियों की शारीरिक क्षमता, धैर्य और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा ली। इस वर्ष की मैराथन में 84 वर्ष के वरिष्ठ प्रतिभागी से लेकर 4 वर्ष के नन्हें बच्चों तक ने सहभागिता कर आयोजन को विशेष बनाया। सभी प्रतिभागियों ने प्राकृतिक सौंदर्य के बीच दौड़ का रोमांचक अनुभव प्राप्त करते हुए फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

संदीपनी विद्यालय घोड़ाडोंगरी में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जागरूकता शिविर आयोजित

बैतूल (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत संदीपनी विद्यालय घोड़ाडोंगरी में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी बृजेन्द्र वर्मा के मार्गदर्शन तथा वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती अनामिका तिवारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। शिविर में वन स्टॉप सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती शिखा भौरासे ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा, हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में उसे छिपाने या संकोच करने के बजाय तत्काल अपने परिजनों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। उन्होंने बालिकाओं और बालकों को पॉक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

सांदीपनि विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिल रहीं आधुनिक और उन्नत शैक्षणिक सुविधाएं प्रभारी मंत्री ने सांची में 40 करोड़ रू लागत से निर्मित शास.सांदीपनि विद्यालय का किया लोकार्पण

सफलता की नई ऊंचाईयों को छूने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें विद्यार्थी: प्रभारी मंत्री पंवार

रायसेन (निप्र)। प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पंवार, सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा द्वारा सांची में नवनिर्मित शासकीय सांदीपनि उ.मा. विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्री पप्पू रेवाराम अहिरवार, कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ श्री कमल सोलंकी, श्री राकेश शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। विद्यालय प्रांगण में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री पंवार ने अपने उद्बोधन में आज सांची में 40 करोड़ रू से अधिक लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है। जिसमें सभी

कक्षाएं आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। यह केवल भवन नहीं है, मॉ सरस्वती का मंदिर है। यह मनुष्य के जीवन का निर्माण करने का पवित्र संस्थान है। यहां देश के भावी नागरिक तैयार होंगे। प्रभारी मंत्री श्री पंवार ने कहा कि विद्यार्थी पूरी लगन और मेहनत से सीखे, पढ़े और अपने भविष्य को गढ़े। शिक्षक भी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए उनके सपनों को नया आकार दें, ताकि विद्यार्थी बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा सभी जिलों में सांदीपनि विद्यालय खोले जा रहे हैं, जहां विद्यार्थी विद्या अर्जन कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री पंवार ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार मिलना भी जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही सही-गलत का ज्ञान देना माता-पिता और शिक्षकों का दायित्व है। उन्होंने सांदीपनि विद्यालय की खूबियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सांदीपनि विद्यालयों में शिक्षा के साथ-साथ कौशल उन्नयन और खेलकूद की विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जिनसे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा निखारकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी ने उपस्थित बच्चों तथा नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सांची को एक ओर महत्वपूर्ण सौगात मिली है। चालीस करोड़ रू से अधिक राशि से बनकर तैयार इस भवन का लोकार्पण हुआ है। यहां सांची ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे है। दूरदराज से बच्चों को विद्यालय आने में परेशानी ना हो, इसके लिए उनके गांव तक बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विधायक डॉ चौधरी ने कहा कि आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों में, बड़े-बड़े निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाएं और शिक्षा मिल रही है। इसी का परिणाम है कि अब माता-पिता बच्चों को निजी स्कूलों के बजाए सरकारी स्कूलों में प्रवेश करा रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ परीक्षा परिणाम में भी वृद्धि हो रही है। सांदीपनि विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। सांची सांदीपनि विद्यालय का गत वर्ष का बोर्ड परीक्षा परिणाम सौ फीसदी रहा है, इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और बच्चे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों के साथ-साथ पीएमश्री विद्यालय भी शुरू किए जा रहे हैं।

सरकार से नहीं बनी बात, सड़क पर जमे किसान

- राजधानी भोपाल में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ बसों पर चढ़े
- सड़क पर दाल-बाटी बनाई, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, सीएम हाउस जाने पर अड़े

भोपाल। मूंग खरीदी, ई-टोकन सिस्टम समेत अन्य मांगों को लेकर भोपाल में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को एमपी नगर के पास वीर सावरकर सेतु पर पुलिस ने रोक दिया। बसों की चार लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। कुछ किसान पहले बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे, जिन्हें पुलिस ने समझाइश देकर नीचे उतार दिया। इसके बाद किसान वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर कुछ किसान अर्धनग्न होकर विरोध जता रहे हैं और सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगें पूरी करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ किसान रातभर जागने के बाद आराम करते नजर आए। दाल-बाटी बनाकर सड़क पर ही लंच का इंतजाम किया। किसानों के समर्थन में जेन-जी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। किसानों ने सरकार की 'सद्बुद्धि' के लिए हवन भी किया और आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी है। इससे होशंगाबाद रोड और आसपास के इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने नर्मदापुरम् रोड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

सीएम बोले- मंत्रियों का दल किसानों से बातचीत करेगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर संवाद के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल मंत्रियों का दल किसानों से बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों के साथ है, लेकिन आम जनता को परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। भोपाल में किसानों के धरना-प्रदर्शन के चलते नर्मदापुरम रोड पर यातायात प्रभावित हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार 28 जुलाई शाम 6 बजे से आरआरएल तिराहा ब्रिज के उतार पर किसान आंदोलन जारी है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों का सीधा आवागमन संभव नहीं है। लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। नर्मदापुरम जाने वाले वाहन कोलार गेस्ट हाउस तिराहा, 6-लेन रोड, होली क्रॉस स्कूल तिराहा, अमरावत कला और मंडीदीप होकर जा सकते हैं। मंडीदीप से भोपाल आने वाले वाहन 11 मील बायपास, नंदी चौराहा, खजूरी कला, एसओएस रोड, पिपलानी और बोर्ड ऑफिस मार्ग का उपयोग करें। मिसरोद, कोलार, चुनाभट्टी, बागमुगालिया और एम्स क्षेत्र के लिए भी वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। वहीं आईएसबीटी से नर्मदापुरम्, बैतूल और जबलपुर जाने वाली बसों को बायपास मार्ग से संचालित किया जा रहा है। यात्रियों से घर से निकलने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन का ध्यान रखने की अपील की गई है।

एमपी में पदोन्नति नियमों पर बढ़ा विवाद

गृह विभाग के अधिकारियों ने उठाए सवाल, सरकार एक्टिव

भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब दस साल बाद शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया अब विवादों में घिरती जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नियमों की अनदेखी और उनकी मनमानी व्याख्या करने के आरोप लग रहे हैं। कमर्शियल टैक्स विभाग के बाद अब गृह विभाग के अधिकारियों ने भी पदोन्नति नियम-2025 के प्रावधानों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए गृह विभाग की सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के अनुरूप पदोन्नति नहीं होने से सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के हजारों कर्मचारी एवं अधिकारी पदोन्नति से वंचित रह गए हैं।

पुलिस विभाग की पदोन्नति पर सबसे ज्यादा सवाल- प्रदेश में सबसे अधिक पदोन्नति पुलिस विभाग में हुई है। सरकार के अनुसार पुलिस महकमे में करीब 25 हजार पदोन्नतियां की गई हैं, जिसकी मुख्यमंत्री भी सार्वजनिक रूप से सराहना कर चुके हैं। हालांकि अब पदोन्नति से वंचित अधिकारी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया और अब गलती स्वीकार करने के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रभावित अधिकारी मामले को लेकर न्यायालय जाने की तैयारी में हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 की कंडिका-6 के अनुसार यदि किसी चयन वर्ष की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक समय पर नहीं हो पाती है, तो अगली बैठक में सबसे पहले उस लंबित चयन वर्ष की अलग चयन सूची तैयार की जानी चाहिए। इसके बाद वर्तमान और आगामी रिक्तियों के लिए नई चयन सूची बनाई जानी चाहिए। आरोप है कि अधिकांश विभागों ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया और वर्ष 2025 की रिक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया की बजाय बाद के वर्षों के आधार पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 जून 2025 को लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी किए थे। इसके बाद 30 जून 2025 को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया कि- वर्ष 2026 में होने वाली डीपीसी के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2020-21 तक की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) को आधार बनाया जाएगा।

चार श्रम संहिताओं के अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत म.प्र शासन, श्रम विभाग द्वारा समुचित सरकार के रूप में चार राज्य नियमों को लागू किया जाना है। श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वेतन संहिता नियम 2026, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध नियम 2026, मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम 2026 और मध्यप्रदेश उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियम 2026 राज्य नियमों के प्रारूपतैयार किये गये हैं।

27 जुलाई 2026 को आयोजित वरिष्ठ सचिव समिति द्वारा उपरोक्त प्रारूप नियमों का सूक्ष्मता से परीक्षण एवं अध्ययन करने के लिये एवं नियमों को अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिये राज्य शासन द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठनश्री अमित राठौर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर की अध्यक्षता में किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में श्री जॉन किंग्सली सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को सदस्य बनाया गया है। श्री रघुराज राजेन्द्रन सचिव श्रम को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

समिति के समक्ष श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप नियमों पर श्रमायुक्त द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। समिति द्वारा प्रारूप नियमों का अनुमोदन किए जाने के उपरांत उन्हें वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा प्रारूप नियमों का विवरण 7 दिवस के भीतर श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का पुनर्गठन

भोपाल। राज्य शासन ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में पुनर्गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख है कि भारत सरकार की योजना 'राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)' अंतर्गत कृषि उपज मंडी समितियों को सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित गाइडलाइन्स अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को 'राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)' योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया है। समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, वित्त और डॉ. एस.के. सिंह, उप कृषि विपणन सलाहकार, मंडी विकास एवं सुधार प्रकोष्ठ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को आवश्यकता अनुसार विशेष आमंत्रित किए जा सकेंगे। यह समिति स्थायी है जो राष्ट्रीय बाजार (ई-नाम) परियोजना के प्रचलन में होने तक कार्यरत रहेगी। समिति के कार्य के अंतर्गत प्रदेश की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना में सम्मिलित किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों (डी.पी.आर) का परीक्षण, स्वीकृति तथा अनुशंसा सहित अपर सचिव (विपणन), भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने संबंधी कार्य करेगी। समिति द्वारा निजी मंडी प्रांगण, निजी संग्रहण/क्रय केन्द्र, डीम्ड मंडी प्रांगण, यदि कोई हो तो के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना के पोर्टल का उपयोग करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार एवं स्वीकृति संबंधी कार्य भी कर सकेगी।

बालाघाट में 24 घंटे में 3 इंच बारिश, नदी-नाले उफान पर

एमपी में स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम ऐक्टिव, 15 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में इन जिलों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक, प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मजबूत मौसम प्रणाली बनी हुई है। यह सिस्टम ओडिशा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश कराएगा। इसके बाद इसके धीरे-धीरे कमजोर होकर अवदाब और फिर निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, कटनी, मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी सहित कई जिलों में भी कहीं हलकी तो कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है।

कई हिस्सों में बारिश का असर दिखने लगा

इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का असर भी दिखने लगा है। ग्वालियर में बुधवार सुबह झमाझम बारिश से लोगों को कई दिनों की गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं बालाघाट में दो दिनों से लगातार बारिश के कारण बीते 24 घंटे में करीब 3 इंच पानी गिरा। इससे दैतबर्रा-मंगलेगांव पुल, टोंडिया नाला और थानेगांव का नाला उफान पर आ गए। सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों पर आवागमन रोक दिया गया, लेकिन कुछ लोग अब भी जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। टोंडिया नाले का पानी एक ढाबे में भी घुस गया। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक धर्मेंद्र अगासे ने बताया कि 30 जुलाई को भी जिले में बहुत भारी बारिश, बिजली, आंधी-तूफान और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

बारिश की तस्वीर सुधरने की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार, अब तक प्रदेश में औसत 13.6 इंच (345.9 मिमी) बारिश हुई है, जबकि 16.5 इंच (418.4 मिमी) पानी गिर जाना था। इस तरह 2.9 इंच यानी, 17 प्रतिशत बारिश कम हुई है। दूसरी ओर, पूर्वी हिस्से में 18 प्रतिशतऔर पश्चिमी हिस्से में 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश होने से यह तस्वीर सुधर सकती है। मौसम एक्सपर्ट नायक ने बताया कि वर्तमान में एक्टिव सिस्टम का असर 1 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान कई जिलों में अति भारी बारिश भी हो सकती है।

इन 47 जिलों में औसत से कम बारिश

अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बैतूल, दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मुरैना, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा। वहीं, 8 जिले- भोपाल, भिंड, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, मंदसौर, राजगढ़ और सीहोर में औसत से ज्यादा पानी गिर चुका है। देवास में 29त्न बारिश ज्यादा हुई है।

जून के बाद जुलाई में भी आंकड़ा कम चल रहा

मौसम विभाग के अनुसार, जून में कम बारिश हुई, लेकिन जुलाई की शुरुआती दिनों में तेज बारिश होने से यह बढ़ गया। बाद में लगातार 9 दिन से तेज बारिश नहीं होने से लगातार चौथे दिन से आंकड़ा माइनस में आ गया है। बता दें कि इस महीने पूरे मानसून की एक तिहाई बारिश का ट्रेंड है। जैसे- भोपाल में 39 इंच सामान्य बारिश है तो 14 इंच बारिश जुलाई में होती है। बड़े शहरों में जबलपुर ही ऐसा है, जहां सबसे ज्यादा 17 इंच से ज्यादा बारिश होती है। जुलाई के महीने में ही प्रदेश में कोटे की 40 प्रतिशत तक बारिश होती है।

उच्च शिक्षा में प्रवेश का कल अंतिम अवसर

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। प्रदेश के शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 31 जुलाई 2026 अंतिम तिथि निर्धारित है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी प्रवेश प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें।

प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का उत्साह निरंतर बना हुआ है। अब तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं NCTE पाठ्यक्रमों में लगभग 5 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। इनमें कला संकाय विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है, जहाँ 2,26,090 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। विज्ञान संकाय में 1,32,127, वाणिज्य संकाय में 64,704, विधि संकाय में 21,130 तथा NCTE पाठ्यक्रमों में 46,566 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि विधि संकाय में पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में प्रवेश संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, जो विद्यार्थियों के बीच विधि शिक्षा के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है।

प्रदेश के अनेक शासकीय महाविद्यालयों में लोकप्रिय पाठ्यक्रमों की अधिकांश सीटें भर चुकी हैं और अंतिम दिनों में भी प्रवेश प्रक्रिया तेज़ी से जारी है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सहायता केन्द्र एवं हेल्पडेस्क सक्रिय हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और 31 जुलाई से पहले ही अपनी पसंद के महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित कर लें।

'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान को मिली वैश्विक पहचान

बड़वानी पुलिस की अभिनव पहल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, 16 हजार से अधिक चित्रों और स्लोगनों के माध्यम से विद्यार्थियों ने दिया नशामुक्ति का संदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व तथा पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के मार्गदर्शन में प्रदेशमें संचालित 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' अभियान जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से संचालित इस अभियान को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। अभियान के अंतर्गत बड़वानी एवं बुरहानपुर जिलों में विद्यार्थियों की अभूतपूर्व सहभागिता ने न केवल जन-जागरूकता का नया आयाम स्थापित किया है, बल्कि प्रदेश को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित भी किया है।

बड़वानी पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में नशामुक्ति विषय पर चित्रकला एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों द्वारा 16 हजार 700 ड्राइंग शीट्स पर तैयार किए गए चित्रों एवं स्लोगनों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इस अभिनव पहल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा मान्यता प्रदान करते हुए बड़वानी पुलिस का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

बावनगजा में आयोजित समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने पुलिस अधीक्षक श्री पद्म विलोचन शुक्ल को मेडल एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसी क्रम में बुरहानपुर पुलिस द्वारा जिले के 113 विद्यालयों के 32 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ अपने हाथों से नशामुक्ति संबंधी संदेश लिखकर हस्ताक्षर किए तथा नशे से दूर रहने एवं समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक जनभागीदारी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो एवं अन्य प्रमाण सत्यापन के लिए प्रेषित किए गए हैं।

दोनों जिलों में आयोजित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे के विरुद्ध अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति और संकल्प के जरिए समाज को सकारात्मक संदेश दिया।